SHORT DURATION DISCUSSION

On Drought Situation in many parts of the Country - contd.

श्री अभय कांत प्रसाद (झारखंड) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पहली बार इस सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया है । महोदय, हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है । सत्तर प्रतिशत से भी ज्यादा लोग यहां कृषि पर निर्भर हैं । हमारे किसान आज भी पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं जिसमें वर्षा का जल सबसे प्रमुख है । नियमित वर्षा न होने से सूखे की स्थिति बनती है । यद्यपि हम तीन तरफ से सागर से घिरे हुए हैं । हमारे एक तरफ हिमालय पर्वत है जो साल भर बर्फ से ढका रहता है। बीस से ज्यादा बड़ी नदियां हैं, सैकड़ों नाले और अन्य नदियां हैं जिनसे हमें सिंचाई का साधन प्राप्त हो सकता है । उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आदि राज्यों में मानसून के नहीं आने से सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

हालांकि मौसम विभाग के महानिदेशक ने परसों माननीय कृषि मंत्री को यह आश्वासन दिया है कि विलम्ब से ही सही लेकिन मानसून आ रहा है। ईश्वर करे उनकी भविष्यवाणी सही साबित हो। हालांकि मौसम विभाग की भविष्यवाणियों को लेकर हम सारे लोग सशंकित रहते हैं।

मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश के 36 मौसम प्रखण्डों में से 25 में अब तक मानसून नहीं पहुंचा है, जो चिंता का विषय है। स्थिति को लेकर स्वयं कृषि मंत्रालय भी काफी चिंतित है। वर्षा न होने से मुख्य रूप से सोयाबीन और ज्वार की फसल को काफी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश की सोयाबीन को लगभग 40 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। समझा जाता है कि सूखे का सबसे ज्यादा प्रभाव राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के भी कुछ क्षेत्रों में पड़ा है। देश का किसान इस स्थिति को लेकर काफी चिंतित है। देश में बार बार सूखा के पड़ने से लोग काफी पीड़ित हैं और इसके कारणों के विवरण में मैं नहीं जाना चाहता हूं। इस बारे में विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। खास करके जंगलों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ता प्रदूषण, जमीन पर आबादी का बढ़ता बोझ, ये सभी इसके लिए जिम्मेवार हैं। 33 प्रतिशत जमीन पर जंगल होने चाहिए। लेकिन आज जमीन पर 13 प्रतिशत से भी कम जंगल हैं जिससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हमें सूखे के कारणों पर अभी नहीं जाकर इस समस्या से निपटने के लिए ध्यान देना चाहिए। आए दिन देश के किसी न किसी भाग में सूखा पड़ता है। सूखा पड़ने के बाद ही हमारी सरकारी मशीनरी सक्रिय होती है। कई तरह के सूखा राहत कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। आपात योजनाएं भी चलायी जाती हैं और इन योजनाओं से किसानों को राहत भी मिलती है पर उनके पूरे नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती है। ऐसी वित्तीय स्थिति भी नहीं है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि सूखे से निपटने के लिए दो तरह की रणनीति बनायी जाए, एक दीर्घकालिक और दूसरी अल्पकालिक। दीर्घकालिक योजना के तहत सरकार को देश की सभी बड़ी बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जो प्रसिद्ध दस्तूर योजना है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार ने इसे बहुत खर्चीला कहकर खारिज कर दिया था। मेरी दृष्टि से आज भी यदि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बाढ़ और सुखाड़ के प्रति वर्ष होने वाले प्रकोप से मुक्ति पाई जा सके तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। शुरुआत हमें सिर्फ कुछ गिनी चुनी नदियों को जोड़कर करनी चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव है कि सूखे से निपटने के लिए केंद्र में एक स्थायी मशीनरी स्थापित की जाए। केंद्रीय सूखा आयोग या प्राधिकरण जैसा कोई स्थायी संगठन बनाया जाए जो वर्षा और सूखे की स्थिति पर बराबर नजर रखे और उससे निपटने के लिए कारगर कदम उठाए। उसी तरह से अल्पकालिक उपायों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे सूखा राहत योजना, काम के बदले अनाज के कार्यक्रम या लाल कार्ड, इन सारे कार्यक्रमों को पारदर्शी बनाया जाए और इन क्षेत्रों में जाकर काफी जांच पड़ताल करके जो उपेक्षित लोग हैं उनको इसका लाभ दिया जाए।

किसानों का सरकार के राहत कार्यक्रमों के प्रति विश्वास पैदा किया जाए और सूखे से निपटने के लिए हमें अभी से ही आपात योजना पर काम शुरू कर देना चाहिए ताकि देश के किसी भी भूभाग को अगले दस-पन्द्रह दिनों में अगर सूखाग्रस्त घोषित करना पड़े तो तत्काल वहां पर राहत शुरू हो जाए, अन्यथा प्रायः यह देखा जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष को सूखागस्त घोषित किए जाने के काफी देर बाद वहां राहत कार्य शुरू होते हैं।

सरकार से मेरा यह भी आग्रह है कि सूखे से निपटने के उपायों के बारे में किसानों को सूचित करने के लिए रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों का उपयोग किया जाए। और उसे निपटाने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखा जाय । महोदय, बड़ी संख्या में हमारी ग्रामीण जनता वर्षा के लिए कई प्रकार के अंध-विश्वासों में पड़ जाती है । उस स्थिति से भी हमें बचना है । यदि हम सूखे को पूरी तरह से नहीं रोक सकते तो कम-से-कम इस से होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने की रणनीति तो बना सकते हैं । महोदय, सूखे के खिलाफ लड़ाई तभी जीती जा सकती है जबकि हम इस से बचाव के तरीकों और लोगों को इस से निपटने के लिए तैयार करने के बीच एक संतुलन बना सकें । महोदय, हमारे यहां एक कनाडा डैम है जिस में झारखंड की हजारों एकड़ जमीन गयी और लाखों लोग विस्थापित हुए, लेकिन उस डैम से जो सिंचाई होती है, उस डैम से जो बिजली बनती है, उस सिंचाई और बिजली का लाभ पश्चिमी बंगाल के लोगों को मिलता है । उस डैम के लिए जमीन झारखंड के लोगों की गयी, लेकिन उस का 99 परसेंट लाभ बंगाल को मिलता है । महोदय, वर्ष 1956 में डा0 श्रीकृष्ण सिंह और विधान चंद राय जो कि तत्कालीन मुख्य मंत्री थे, के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जिस के तहत हमें जितना पानी और बिजली मिलनी चाहिए थी, वह आज तक प्राप्त नहीं हो रही है । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि चूंकि हमें उस एग्रीमेंट के तहत पानी और बिजली नहीं मिल रही है, इसलिए नए सिरे से उस एग्रीमेंट का रिव्यु होना चाहिए। यदि झारखंड को उस एग्रीमेंट के तहत पानी, बिजली का उचित हिस्सा मिले तो इस तरह से हम सुखाड़ से राहत प्राप्त कर सकते हैं । महोदय, सुखाड़ उतनी बड़ी समस्या नहीं है कि हम उस का समाधान न निकाल सकें । हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस समस्या का मुकाबला कर सकते हैं । महोदय, हमारे यहां एक मैथन डैम है जिस का एग्रीमेंट भी उस एग्रीमेंट की तरह हुआ था । इन सभी डैम्स का फिर से रिव्यु होना चाहिए ताकि हमें अपने हिस्से का उचित शेयर मिल सके । महोदय, आज हमारे झारखंड में किसान एक ही फसल पर निर्भर करते हैं । वहां कोई रबी की फसल नहीं होती है और मकई, गुंदली व मड़वा जैसी खरीफ की फसल भी मर रही है । वहां बिचरा भी समाप्त हो गयी है । इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि झारखंड में सिंचाई की विशेष व्यवस्था की जाए । वहां दीर्घकालिक योजना के तहत बड़ी प्यास के कुएं और जगह-जगह डैम बनाए जाए, चैक डैम

बनाए जाएं और पोखरा का निर्माण होने से आने वाले समय में हम सुखाड़ की स्थिति का मुकाबला कर सकते हैं ।

आप ने मुझे बोलने का समय दिया, इस के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Now, Mr. R. Kamaraj. You have eight minutes.

*SHRI R. KAMARAJ (Tamil Nadu): Mr. Vice Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to take part in the discussion on the drought situation in the country, on behalf of AIADMK.

Our Country has 328.7 million hectares of land area, out of which about 142.2 million hectares land is under cultivation. Out of that only 40% of lands get irrigation facility. Of the total population of 103 crore, about 72% people still depend on agriculture. Several statistics show that due to drought, flood, cyclone, earthquake and other vagaries of nature, 22 districts are affected every year. Drought alone affects 68% of our land surface causing misery to about 50 million people.

Sir, this is what the annual statistics reveal. Last year, we had a satisfactory monsoon. Even then, crops in over 67.44 lakh hectares spread over 167 districts in 5 states were affected. But this year the monsoon has completely failed. It is very disturbing. I am reminded of the Madras famine of 1876-78. It is a grim situation indeed. The report of the United Nations Population Project is shocking. According to the report there are 29 nations in the World facing water scarcity as of now. The report says that in the year 2025, 34 nations would be facing shortage of even drinking water. Shockingly, India too figures in that list of nations. If drinking water is going to be scarce, what about water for other needs? The late lamented Chief Minister of Tamilnadu, Puratchi Thalaivar Dr.M.G.R. sang in a movie,

"What resource our country is devoid of
Why stretch out our arms to other countries."

I quote this because, we have enough natural resources. We have water resources to sustain us. Yet why we face drought repeatedly? We have gone through 9 Five-Year Plans. We are entering the 10th Plan now. The Hon'ble Minister should tell the House whether the Government have

* English translation of the original speech in Tamil.

any mega project to harness the water from available sources for hard times at least in the 10th Plan.

Sir, reports say that we get about 1880 cubic kilometre water annually from surface water sources such as rivers. But we utilise only 700 cubic kilometres of water out of this. About 1180 cubic kilometre water runs waste. So also, the quantum of water received through rains in a year on an average is said to be over 4000 cubic kilometres. Of this only 600 cubic kilometres water go down the earth. In all we use only about 1120 cubic kilometre water out of 4000 cubic kilometres. That is to say we do not utilise about three fourth of the water received. That is why the country is facing severe drought today. I request the Hon'ble Minister to inform the House about the projects and schemes launched for harnessing and storing water for future use.

Sir, in so far as Tamilnadu is concerned, it is affected by both flood and drought in the same year. In February this year we had unusual and heavy rains in Tamilnadu resulting in flood, damaging crops and houses. Today Tamilnadu is facing drought because we did not get our due share of Cauvery water. We did not get our share of water from the month of April.

SHRI M.V. RAJASHEKARAN (Karnataka): Sir, he is unnecessarily bringing the Cauvery water dispute here. If he is mentioning the Cauvery water dispute, then we would like to answer...*(Interruptions)*...We would also like to place our case before the House. He should not be allowed to mention anything about it ...*(Interruptions)*...

SHRI H.K. JAVARE GOWDA (Karnataka): Where is water in Karnataka? If we get water, then we would be very happy to release it. What would we do by keeping water with us?...*(Interruptions)*...

SHRI R. KAMARAJ: Karnataka is responsible for both flood and drought in Tamilnadu.

SHRI M.V. RAJASHEKARAN: He is trying to mislead the House...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Hon. Members, we are discussing here a very serious issue. I request all the hon. Members to bear in mind the seriousness of the issue...*(Interruptions)*... Let not any controversial issue be brought here.

SHRI R. KAMARAJ: Sir, there is severe drought in the Cauvery delta. *Kuruvai* paddy crop could not be raised even in one sixth of the total area raised every year. The traditional *Samba* crop has became uncertain. Tamilnadu is facing drought on one side and financial constraints on the other side. That is why the Hon'ble Chief Minister of Tamilnadu Dr. Puratchi Thalaivi Amma has launched a scheme at the cost of Rs. 164.8 crore for the benefit of Cauvery delta farmers and agricultural labourers. The significance of this scheme is that, the works would be executed only through human resource, thus providing employment opportunity to the people.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Mr. Kamaraj, you have already taken nine minutes. Time allotted to your party is only eight minutes. Now, you kindly conclude your speech.

SHRI R. KAMARAJ: Okay, Sir. Today, various schemes at a cost of Rs. 164.18 crore have been undertaken to provide relief to the people. There have been no rains in the southern districts of Tamilnadu. These districts do not get water from periyar dam because of the dragging problem. The districts that grow coconut trees are facing problems. Due to drought over 307622 coconut trees are drying up. The growers are in a hapless situation. For growing one coconut tree, we have to spend 250 rupees. The Government of Tamilnadu has sought 7.69 crore rupees for growing coconut trees afresh in those districts. I request the Hon'ble Minister to kindly sanction the amount.

Sir, for the centrally aided Macro Management Mode, Rs. 45 to 46 crore was allotted till last year. It is learnt that the amount has been reduced to Rs. 42 crore this year. Since this is a drought-affected year I appeal to the Government to allocate Rs. 50 crore this year. Under the Planning Commission Project known as Water Resources Consolidation Project, structures for recharging water into the earth are being set up in 13000 places in Tamilnadu. Wasteland Development has been undertaken in Tamilnadu with a target of developing 20 lakh hectares of wasteland at the rate of 5 lakh hectares per year. The Hon'ble Chief Minister of Tamilnadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma has been launching such schemes to provide relief to people. Therefore, I request the Government to provide adequate funds to Tamil Nadu Government to provide relief to the drought hit people of Tamilnadu.

PROF. M. SANKARALINGAM (Tamil Nadu): Hon. Vice-Chairman, Sir, I wish to point out one point, that is, we are now attending the

Monsoon Session of the Parliament. But where to see the monsoon, is a question before us. We are experiencing very hot days, as hot as anything. This situation is prevailing in the whole of the country. The Northern region, especially Rajasthan, Orissa and Madhya Pradesh, is facing a very grave situation. 70-75 per cent of our population is engaged in agriculture. Without water how could they produce grains; how could they live, how could we expect any production from them? This is a very big question before us. Since my time is very limited, I would not deal with the other parts of our country. I would join with the other hon. Members who have explained the situation of their respective States. I would like to stress on the situation in Tamil Nadu. Kavery Delta area is our paddy belt. A yield of about 17 lakh tonne paddy crop was expected. But, only 2-3 lakh tonnes have been produced. About 40 lakh hectares is dry land. The people are facing crisis there. The whole of Tamil Nadu is also facing crisis. Not only the Kavery Delta, but Coimbatore, Madurai, Tirunelvelia, Ramnathapuram, Kanyakumari, Pondicherry, everywhere the situation is the same. This is due to failure of monsoon. The South-West monsoon is expected to give rain in June-July. We are now in the middle of July. But there is no rain. The Meteorological Department, especially the Bangalore-based department, had indicated in their report that this year we would get more rains. But their calculation failed. Our country also failed in the agricultural field. So, I would like to request the hon. Minister of Agriculture who is a son of a veteran agriculture leader of our country. He also has the experience of research in that field. As the hon. Member, Mr. Ahluwalia, has said, he is a worthy son of a worthy father. Now, he is our worthy Minister. At this time of crisis, he is holding that department. I request the hon. Minster to look into the matter and relieve the Indian farmers from this distress. Sir, I have mentioned something with regard to Tamil Nadu. The hon. Member from Tamil Nadu, who spoke before me, told that thousands of coconut trees are in the dropping condition. If you go by road, you will see that not only in Coimbatore, but in Madurai, Kanyakumari, thousands of trees are dropping. Kanyakumari and Kerala used to get South-West monsoon, but there is no rain. I come from Kanyakumari district. There are two dams, the Peichiparai Dam and the Peruchani Dam, in Kanyakumari District. During the months of June and July, there used to be surplus water in these dams. But now, it is not even one-thenth. So, in all the five channels, a shift arrangement has been made for release of water. More than 75 per cent of paddy crop there is getting destroyed because of lack of water. This is the situation prevailing, from Kanyakumari to Kashmir. Except some parts, the

whole country is facing a same crisis. I request the hon. Minister to tour the entire country, especially, the drought-affected areas, interact with the experts of paddy growers, get information from them, and find out reasons for this havoc. My feeling is, afforestation is the main reason for this. Our forests were ruined like anything. All our big trees were felled. Illegal transportation is being conducted there, with the connivance of big officials, big people. These people must be put behind bars. Sufficient teeth should be given to the present law. I know, the present law is not capable of controlling these activities. So, I request the hon. Minister to look into the matter and get first-hand information regarding this.

The other point is, during the monsoon season, 75 per cent of the rainwater goes into the sea. Are we not capable of conserving that water? We have to conserve it in dams, but no plan has been drawn up. It has been discussed so many times in the House. We have discussed about the Ganga-Cauvery Project also. But nothing has come out of it, because no attention was given to it. These are long-term plans. Now the position is that, out of the 105 crore people, 80 crore people, that is, 75 per cent of our agricultural population, are at starvation level. They have nothing to fall back on. They have no earning because there is no production. So, what will be the economic position of our country after two or three years? This will have an impact only after three or four years. So, I request the hon. Minister that he should consult other Ministers and come out with some effective measures for generating employment opportunities.

Regarding Crop Insurance, I want to suggest that it must be made a compulsory one. A farmer raises a crop; but he is usually poor and illiterate. So, he will not be in a position to get the insurance form, fill it and submit it at the Insurance Office. So, it is for the Presidents and members of the local bodies to see that all the farmers are covered by the Crop Insurance Scheme. If their crop fails, they should get full compensation for it so that they don't face any peril. This rainwater harvesting, this Crop Insurance Scheme and this saving of forests and trees only will protect our country. So, I request the hon. Minister, and the hon. Prime Minister and other Ministers, to hold discussions on this matter and save our country and save our people. With these words, I conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Shri Vijay Singh Yadav. Mr. Yadav, you have eight minutes.

4.00 p.m.

श्री विजय सिंह यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, सुखाड़ पर मुझे बोलने के लिए आपने जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं । सूखा पर माननीय श्री जनेश्वर मिश्र जी, सुरेश पचौरी जी तथा अन्य सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उन भावनाओं से अपने आपको संबद्ध करता हूं । आज सुखाड़ पर बोलने का जो दिन आया है, यह बहुत गंभीर मामला है । हम भाषण देते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है लेकिन हम उसी प्रधानता को समाप्त करते जा रहे हैं । महोदय, यह मानसून सत्र चल रहा है । इस मानसून सत्र में मानसून गायब हो गया - जैसे ही सत्र शुरू हुआ, मानसून समाप्त हो गया - यह बड़े ही दर्द की बात है । एक समय था जब द्वापर में भगवान कृष्ण और भगवान राम के राज में, जिसे राम राज कहते थे, उस रामराज में सभी जन, पशु-पक्षी राज करते थे । भगवान कृष्ण के समय इंद्र देवता धरती को इतना जल मग्न कर देते थे कि जन जन अमन चैन से अपना जीवन व्यतीत करता था । महोदय, किसान लोग गांव में कहते हैं कि जब बहू-बेटी गांव में आती है तो उसका लक्षण देखा जाता है - लक्षण और कुलक्षण देखे जाते हैं। किसान के घर में जब शादी-ब्याह होता है या झाड़ू भी लिया जाता है तो उसको भी लक्षण और कुलक्षण कहा जाता है । इस देश में ऐसे लक्षण वाले लोग हैं कि भगवान इंद्र समाप्त हो गये हैं । लोग इन्द्र भगवान को जप रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और इंद्र भगवान गायब हो गये हैं । हमारे देश के किसान भूख की कगार पर हैं । महोदय, अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहला लक्ष्य किसान को बनाया और उन्होंने अपना सारा ध्यान कृषि पर दिया । उन्होंने पूरे देश में कृषि का, खेती का जाल बिछाया, नहरें बनाईं, नाले बनाए, खेत खलिहानों को चारों तरफ से घेर करके नहर-पुखड़ा, सब बनाने का काम किया लेकिन हमारे देश के जो शासक बैठे हैं, वे सारे नहर-पुखड़ा को भरने का और रोड बनाने का काम कर रहे हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि इन नालों को फिर से शुरू किया जाए क्योंकि अंग्रेजों का पहला लक्ष्य था कृषि । उन्होंने उस पर ध्यान देकर तीन सौ वर्ष तक भारत पर राज किया और हम चालीस-पचास वर्षों में इसको खोते जा रहे हैं । हम नदी नालों को समाप्त करते जा रहे हैं इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि वह इस ओर ध्यान दे, नदी नालों पर ध्यान दे ताकि हम कृषि का उत्पादन कर सकें । महोदय, पहले हमारा दूध उद्योग भी बहुत बड़ा था । वह भी अंग्रेजों ने किया । उस दूध उत्पादन को हम समाप्त करते जा रहे हैं, कृषि को भी समाप्त करते जा रहे हैं इसलिए भगवान इंद्र को खुश करने के लिए आज हमारे देश में हमारे किसान, हमारी माताएं-बहनें निर्वस्त्र होकर हल चला रही हैं, भगवान का भजन कर रही हैं कि इंद्र भगवान आइए लेकिन सरकार दर्शक बनी हुई है । आप उन पर थोड़ा सा तरस खाइए कि हमारे देश की मां-बहनें निर्वस्त्र होकर खेत में पूजा कर रही हैं, भगवान इंद्र की प्रार्थना कर रही हैं कि वह बरसें । ...**(व्यवधान)**...आप बीच में मत बोलिए। इसलिए हमारा सुझाव है कि कम से कम किसानों के लिए जो हमारी सरकार कहती है कि एफ.सी.आई. का भंडार भरा हुआ है, उनको राहत देने के लिए ए.पी.एल, बी.पी.एल. से जितना भी हो सके, राहत कार्य शुरू करे । महोदय, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। इस संबंध में राहत कार्य कैसे चलाया जाए, उस संबंध में मैं सुझाव देना चाहता हूं । मंत्री महोदय हमारे बड़े भाई हैं और हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह जी को मैं नमन करता हूं, वे पूरे देश के किसानों के मसीहा थे । आज इस सदन में उनकी याद आ रही है । महोदय, जन-जन हमारे चरण सिंह जी का नाम याद रखता था । हमारे बड़े भाई, हमारे मंत्री महोदय उस विभाग से संबंधित हैं, वे किसानों के मसीहा बनें, उनके मार्ग पर चलें, यह मेरा सुझाव है । एक एक

किसान मर रहा है, उसका जरा भी तरस सरकार को नहीं है, सरकार दर्शक बनी हुई है । मेरा सुझाव है कि इस पर विशेष रूप से पूरे देश में ध्यान दिया जाए। उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश इलाकों में आजकल किसान टकटकी बांधे आसमान की ओर देख रहा है । आषाढ़ का अंत निकट है, सावन आने को है किंतु आसमान अभी तक सूना है । बारिश के बिना खेत सूख रहे हैं, अकाल की आशंका से चेहरे मुरझा गए हैं । मौसम विभाग की मानें तो मानसून आने में अभी एक हफ्ता और लगेगा । यदि हफ्ते भर में मानसून आ गया तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से, राजस्थान तथा उत्तर सौराष्ट्र में बरबादी के कगार पर खड़ी फसल बच जाएगी । इंद्र देवता रूठे रहें तो बात बिगड़ जाएगी । पिछले तीन साल से सूखे की मार झेल रहे मध्य प्रदेश व राजस्थान में हालात काबू से बाहर हो सकते हैं । फल व सब्जियों की कीमतों में वृद्धि से मानसून की कमी का अहसास होना शुरू हो गया है । देश में सामान्य वर्षा के वक्त भी कुछ इलाकों में सूखा पड़ता है । बारिश देर से होने का मतलब है किसान की लागत बढ़ना । ट्यूबवेल चलाकर खेतों को पानी देना पड़ता है । देरी से बुवाई वाले बीज लगाने पड़ते हैं । इसका काफी असर उत्पादन पर भी पड़ता है । इस बार मानसून का कोपभाजन जिन राज्यों को बनना पड़ रहा है, वे देश के खाद्यान्न उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं । उत्तर भारत में सूखा पड़ने के कारण इस बार कृषि विकास दर का लक्ष्य पाना कठिन होगा । वैसे भी कृषि के क्षेत्र का सीधा असर उद्योगों पर पड़ता है । महंगाई बढ़ने के साथ किसानों की क्रय शक्ति कम होने का प्रभाव अन्य सभी आर्थिक गतिविधियों पर भी निश्चित तौर पर पड़ता है । आज़ादी के 55 वर्ष बाद भी देश की साठ प्रतिशत से भी अधिक खेती बारिश पर ही निर्भर करती है, यह चिंता का विषय है । केवल चार प्रतिशत भूमि ही नहरों से सींची जाती है । अधिकांश किसान सिंचाई के ट्यूबवेल के भरोसे रहते हैं । वर्षा के अभाव तथा तेज गरमी के कारण मिट्टी से नमी भी कम हो चुकी है । ऐसे में खरीफ की धान, खाद्य तेल, मक्का, ज्वार आदि फसलों की बुवाई पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ।

महोदय, मैं बिहार से आता हूं । बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र 173.8 लाख हेक्टेयर का लगभग 68.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है । इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में से 44.47 लाख हेक्टेयर मात्र उत्तर बिहार में पड़ता है जबकि उत्तर बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 53.5 लाख हेक्टेयर है । महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार का जब से बंटवारा हुआ तब से उसको कोई मदद नहीं मिली । वह बाढ़ और सुखाड़, दोनों से ग्रसित है । उत्तर बिहार बाढ़ से ग्रसित है और बिहार की माननीया मुख्य मंत्री राबड़ी देवी दुर्गा के रूप में चारों तरफ सारे किसानों को, जन-जन को राहत पहुंचा रही हैं लेकिन केन्द्र सरकार को ज़रा भी तरस नहीं आ रहा है कि वह भी हमारे देश का ही एक राज्य है । महोदय, बिहार पर कल बहस हो रही थी, इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि वह उसे एक विशेष राज्य का दर्जा दे ।

महोदय, बिहार में भागलपुर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, गया, पटना, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल आदि ज़िलों में सुखाड़ है । मैं चाहूंगा कि सरकार एक कमेटी का गठन करके बिहार में भेजे और तहकीकात करके उन लोगों के लिए राहत कार्य चलाए, यह मेरा सरकार से अनुरोध होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): The next speaker is Shri N.R. Dasari. Mr. Dasari, you have only four minutes.

SHRI N. R. DASARI (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to associate myself with the feelings and suggestions of my colleagues who have expressed their anguish over the grave situation which has arisen due to drought and floods in different parts of our country. I would also like to express the solidarity and sympathy of our party, the CPI, to the people affected by drought.

In my own State of Andhra Pradesh, millions of people, in thousands of villages, in large parts of the State, have fallen victims to the severe drought situation, for the second consecutive year. The irrigation tanks, borewells and other water reservoirs, small and big, are dried up totally, in about 890 *mandals*, out of 1126 *mandals*.

In the whole State, there should have been 186 mm of rain, by now, generally. But so far, the rainfall is only about 93 mm; only 93 mm. This is just 50 per cent of the average rainfall in this season. In the coastal region, where, by now, there should have been 175 mm of rainfall, it is only 46 per cent of the normal rainfall, so far.

There are about 11,205 irrigation tanks, small and big, in different regions. But, about 10,000 tanks have already dried up due to the failure of Monsoon. As a result of this grave situation, transplantation has not been done in 32 lakh acres; even where it was attempted, it was not done properly. Under major irrigation projects, out of 117 lakh acres of traditional cultivation, water is supplied only for 15 per cent of the area. Dry crops have been sown only in 38 lakh acres, out of 130 lakh acres of traditionally-sown area.

This, in brief, is the gravity of the situation, which is more severe than ever before in Andhra Pradesh. The drinking water problem has become very acute, and it may aggravate in time to come; and, in some parts, people are compelled to walk as far as 3 kilometres, for potable water. On the top of this, there is shocking power cut in all parts of our State.

I would, therefore, like to request the Union Ministry of Agriculture to take urgent steps, on a war-footing, to pay compensation to the farmers who are likely to fall under serious indebtedness, due to the crop failure, and also to provide alternative jobs under the 'Food for Work' programme to the poor agricultural workers who are the worst hit by the crop failure. This situation brooks no delay. Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABKHAR REDDY): The next speaker is Mr. A. Khan. Mr. A. Khan, there are two more speakers from the Congress, and only 18 minutes are left. So, all of you have to speak within 18 minutes.

SHRI AIMADUDDIN AHMED KHAN (DURRU) (Rajasthan): Sir, I will take only a few minutes.

Thank you very much, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on a very important issue of the day, which not only involves a large part of the country, but also a large population of our country, over 70 per cent of whom live in the rural areas.

Sir, we are all aware, through various sources, including the visual and written media, of the drought situation prevailing in the country, mainly in the Northern States of the country. The problems of drinking water and irrigation is confined not only to the rural areas, but also to the large urban areas. This year, not only there were no pre-monsoon showers; even the Monsoon seems to have totally ignored and avoided this part of the country. In vast areas of Rajasthan, Punjab, U.P., M.P. and other nearby areas, whereas green fields of paddy, flooded with water, usually give us a pleasant sight, we now see only parched and dry fields. While the Meteorological Department is still fumbling with monsoon forecasts, the patience of the farmer is getting exhausted. The farmers in Punjab are planning drastic changes in crop patterns, and are thinking of moving away from paddy to other crops. The U.P. farmer has demanded that the State be declared a drought-hit State. Similarly, Madhya Pradesh and Chhattisgarh are also planning to moveaway from paddy. While the previous speakers have already drawn the attention of this august House to the conditions prevailing in these areas, I wish to draw your kind attention, Sir, particularly to the State of Rajasthan, to which I belong.

Sir, as you are well aware, over 40 per cent of the State is covered by desert and sand dunes. These areas do not have anything like the rabi crops. They are only dependent on the kharif crops, which in turn, are solely dependent on rain. Rajasthan is almost entirely deprived of any natural water resources and river waters. The farmer in Rajasthan depends largely on animal husbandry and cattle and sheep breeding. In the best of times, the farmer in Rajasthan produces foodgrain stocks, to satisfy the requirements of his family for only four to five months, and for the rest of the year, the family has to labour to satisfy their bare needs for food and

clothing. They often, under circumstances as are prevailing now, have to migrate to greener pastures to not only sustain their livestock, but also to labour to earn their livelihood. In the course of such a situation which leads to migration, the livestock, including the high yielding local breeds of cattle, become infertile and often die. During the hot and dry season, though the State Government makes arrangements for drinking water by transporting the same by tankers and trains, yet this is barely sufficient for the human beings only, and the livestock manages to get drinking water only once every two or three days.

Coming to rainfall, in Rajasthan, this year, rains have been scanty in as many as ten districts, like Bikaner, Bharatpur, Dausa, Jaipur, Sri Ganganagar, Jaisalmer, Jodhpur, Kota, and Sikar. There was practically no rainfall in the State during the first 15 days of June, and again, during July Ist to July 15th, whatever rains have come, have given a little respite, and there has practically been no change in the levels of reservoirs as there was no appreciable surface flow of rain water except a little rise in the level of Jawai, Bund Baretha and Mahi dams. There has been no active monsoon in the State since 29th June, 2002, and the overall position of monsoon rainfall from Ist June to 15th July is, to say the least, not satisfactory. Sir, we have to consider the case of Rajasthan as a largely desert State, full of sand dunes, bereft of natural river waters and totally dependent on rain gods. As such, Rajasthan deserves greater consideration from the Centre and the Union Minister of Agriculture. We must appreciate that the Minister of Agriculture has already taken up the matter of scarce rains in this part of the country and bringing expert heads together, to plan out in advance a strategy for the farmer hard-hit by the near drought situation. I am confident that urgent steps would be taken to ensure timely help, as desired by the State Government, by way of credit and subsidies and providing crop insurance for various crops, specially, in respect of rain dependent States, like Rajasthan. Thank you.

श्री सुनील शास्त्री (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, आज मैं एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । आपने मुझे जो यह अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

इस समय उत्तर भारत पूर्ण रूप से सूखे की चपेट में है । मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले एक महीने से मौसम विभाग ने जिस तरह से बार-बार एक आशा की किरण लोगों में जगाई कि वर्षा शीघ्र होने वाली है और वर्षा की आशा में हमारे लाखों किसान भाई इंतजार करते रहे, लेकिन वर्षा न होने के कारण जो आज गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें मैं यह कह

सकता हूं कि अब अगर वर्षा हो भी जाए तो भी जो नुक्सान हमारे कृषि क्षेत्र में किसानों को, और अन्य लोगों को हुआ है उसकी भरपाई कर पाना संभव नहीं हो पाएगा।

आज, जैसा कि अभी मेरे सहयोगी सदस्यों ने अपनी बातों को यहां पर रखा, हमारे वरिष्ठ सदस्य कलराज मिश्र जी कह रहे थे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कई जिले सूखे से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं और किसी प्रकार का जो एक राहत का कार्य उन क्षेत्रों में होना चाहिए वह दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि 42 जिले उत्तर प्रदेश में इस समय ऐसे हैं जहां पर सूखा है उसने पूरी तरह से वहां के किसानों को प्रभावित किया है। मैं यह कहूंगा कि केवल जमीन ही नहीं फटी हुई दिखाई पड़ती है बल्कि किसान पूरी तरह से दुखी हैं और किसान इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है कि यदि किसी प्रकार का सहयोग, सहायता उसे प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से समय पर नहीं मिली तो आने वाला पूरा वर्ष उसके लिए, उसके परिवार के लिए खराब होगा।

आप सब जानते हैं कि खेतिहर मजदूरों की संख्या करोड़ों में है, हमारे खेतिहर मजदूर सीजनल वर्कर्स होते हैं और उनकी जो भी जीविका का साधन है, अगर उपज अच्छी होती है तो उन्हें काम अच्छा मिलता है, उनका जो मानदेय है, उनके जो वेजेज हैं वैं भी उन्हें न्यूनतम वेज अधिनियम जो भारत सरकार का है, उसके अंतर्गत मिल जाते हैं। लेकिन अगर खेती ही, फसल ही पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो मैं कैसे इस बात को कह सकता हूं या मान सकता हूं कि जो हमारे खेतिहर मजदूर हैं जिनकी जीविका इस पर निर्भर करती है उनका भविष्य कितना अधिक अंधकार में नहीं पड़ जाएगा। एक दुखी करने वाली स्थिति उनके परिवार के लिए उत्पन्न हो जाएगी।

यहां पर मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जो नुक्सान इस समय सूखे के कारण आज मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को, हरियाणा को, पंजाब को या देश के अन्य भागों में कुछ जिले हों, उनको हुआ है उसका सीधा असर जीडीपी पर पड़ेगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो हमारा प्रस्तावित 6 प्रतिशत का ग्रोथ रेट है वह भी अवश्य इस नुक्सान के कारण प्रभावित होगा।

मैं यह मानता हूं कि हमारे माननीय कृषि मंत्री ने हाल ही में कुछ बैठकें ली हैं। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की है, मौसम विभाग के अधिकारियों से बातचीत की है। एक संयुक्त सचिव के स्तर पर जहां जहां ड्राउट की समस्या उत्पन्न हुई है, उनका निरीक्षण करना, वहां से रिपोर्ट मंगाना इस सबके बारे में उन्होंने बैठक ली है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर, नेशन एज ए होल, अगर इसमें बैठकर, हम यह नहीं सोचें कि किस तरह से इस दैवी आपत्ति से, नेचुरल कैलामिटी से हम आगे भविष्य में निपटेंगे, अगर आज हम रणनीति उसके संबंध में तैयार नहीं करना शुरू करेंगे ...। तो मैं समझता हूं कि हमारा भविष्य भी इसी प्रकार अंधकारमय रहेगा, इसी प्रकार से बाढ़ आएगी, हमारे किसान भाई परेशान होंगे, इसी प्रकार से सूखा पड़ेगा और हमारे देश की पूरी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी । यहां पर मैं यह कहना चाहूंगा हालांकि एग्रीकल्चर अवश्य स्टेट सब्जैक्ट है, लेकिन मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट को भी इस संबंध में एक पालिसी का निर्धारण करना चाहिए और गाइडलाइन्ज़ बनानी चाहिए । वह तैयार करके अगर समय-समय पर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कहते रहेंगे, उन्हें गाइडलाईंज़ भेजते रहेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में ऐसी समस्याओं का समाधान हम अवश्य निकाल पायेंगे । आपने देखा कि अभी हमारे पूर्व वित्त

मंत्री और वर्तमान विदेश मंत्री जी यहां पर बैठे थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया और हमारी सरकार ने भी बार-बार इस बात पर विशेष बल दिया कि किसानों के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है । उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उपज को बढ़ाने के लिए, हर तरह से हमारी सरकार कटिबद्ध है और हम अपने कार्यक्रम व नीतियां भी इसी प्रकार से बना रहे हैं कि जिसके माध्यम से हम अपने किसानों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान कर सकें । मैं यह कहना चाहूंगा कि उसी कार्यक्रम के अंतर्गत एग्रीकल्चर इंशोरेंस कार्पोरेशन बनाने का फैसला हमारी सरकार ने लिया । जहां एक ओर वह क्रॉप इंशोरेंस करेगी, वही दूसरी ओर कृषि से जुड़े हुए, किसानी से जुड़े हुए अन्य जो कार्य होंगे, उन सब की देखरेख भी उसी कार्पोरेशन के माध्यम से की जाएगी । मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां पर इस तरह की गाइडलाइन्ज़ और एक ऐसी पालिसी निर्धारित की जाए जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह की कुछ पॉवर्ज़ दे, इस तरह के कुछ अधिकार दे, क्योंकि जब तक केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार उन प्रदेशों को या जिलों को सूखाग्रस्त घोषित न करे या जब तक कोई ऑफिशियल एनाउंसमेंट इस संबंध में न हो, तब तक कोई राहत का कार्य भी शुरू नहीं होता और किसी प्रकार की कोई सुविधा किसानों को प्रदान नहीं की जाती । इसलिए मेरा यह कहना है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस प्रकार के अधिकार दे दिए जाएं जिससे कि जहां कि उसके अपने असैसमेंट में, अपना जब वह आकलन करे और स्थिति का जायजा ले तथा उसे ऐसा लगे कि आज स्थिति नाजुक हो रही है, एक सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आज नहीं तो हफ्ते भर बाद, तो वह अपनी एक नीति निर्धारित कर ले तथा उस नीति के माध्यम से, कम से कम जो इमीडिएट रिलीफ है वह प्रदान कर सके, जैसे कि पशुओं के लिए चारा, पीने के पानी की व्यवस्था और वहां पर जो फसलें हैं उनको किस तरह से बचा सकते हैं । इसके लिए मेरा कृषि मंत्री जी से आग्रह होगा कि वह इस ओर ध्यान दें और अगर आवश्यकता पड़ती है तो हर प्रदेश के कृषि मंत्री की एक बैठक केन्द्र में बुलायें, जिसमें इस बात को उनके समक्ष रख कर एक नीति निर्धारित करें जो कि भविष्य में हमेशा लाभदायक होगी । मुझे विश्वास है कि उससे सब को लाभ ही लाभ मिलेगा । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस समय धान की जो हमारी पौध है वह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है । मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, वहां 58 लाख हेक्टेयर में जो धान की खेती होती है, उसका लगभग पचास प्रतिशत नष्ट हो चुका है, उस पर असर पड़ चुका है । गन्ने की फसल पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है । जिनमें मक्का, दाल आदि भी है । इस प्रकार की बहुत सी फसलें हैं जो कि प्रभावित हो रही हैं । आज उत्तर प्रदेश सरकार ने मांग की है और उन्होंने बहुत सी चिंता की बातें हमारे सामने रखी हैं । मैं समझता हूं कि अब प्रदेश सरकारों की मांगों और उनकी कठिनाइयों की तरफ ध्यान देने का समय आ गया है । अभी हमारे सभी माननीय सदस्यों ने उनके अपने यहां पर जो परेशानी है और इस समय जो वहां की स्थिति का जायजा लिया है, उसका एक आंकलन यहां पर प्रस्तुत किया है । मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय कृषि मंत्री जी उन सब बातों पर विचार करेंगे, उन्हें गंभीरता से देखेंगे और जो भी आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है, वे जरूर उठाएंगे । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने खराब पड़े 3500 पंपों को ठीक कराने के लिए जिस आर्थिक सहायता की मांग की है, मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार को उसे पूरा करना चाहिए । साथ-ही-साथ जो कैनाल्स हैं व अन्य सिंचाई के साधन जिन में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, अगर सरकार उस ओर भी थोड़ासा ध्यान देगी तो मुझे विश्वास है कि प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के किसानों को भी राहत मिलेगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रमुख वक्ताओं ने भी इस बात पर चिंता प्रकट की है कि बिजली का संकट एक बड़ा संकट है । मैं कहना चाहूंगा कि आज कम-से-कम उन क्षेत्रों में जहां सूखा पड़ गया है, यह सुनिश्चित करना होगा कि उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति किस तरह से सुनिश्चित की जाए और वहां राहत के कार्य तेजी से चलाए जाएं । महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र कलराज मिश्र जी नहीं कर पाए थे, हालांकि जनेश्वर मिश्र जी ने उसका जिक्र किया था । मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थिति काफी गंभीर है । जनेश्वर मिश्र जी ने अलीगढ़ से गोरखपुर और देवरिया तक की बात की थी, लेकिन मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष तौर से कहना चाहूंगा क्योंकि माननीय कृषि मंत्री श्री अजीत सिंह जी भी उसी क्षेत्र से हैं। महोदय, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूखे के कारण गंभीर संकट है, अतः हमें उस ओर भी विशेष तौर से ध्यान देना होगा ।

महोदय, मैं एक बात सुझाव के रूप में अवश्य कहना चाहूंगा क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जहां तक सूखे का संबंध है, देश में कई बार सुखाड़ और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है । इसलिए हमें विश्व में जिन देशों ने ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं या इम्प्रूवमेंट के लिए प्रबंध किए हैं, उन से सीखने की भी आवश्यकता है । मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान अमेरिका की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जहां कि ड्राउट की सिचुएशन को टैकल करने के लिए वहां की एक यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक नेशनल ड्राउट मिटीगेशन सेंटर गठित किया गया है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Please conclude. There is one more speaker from your party.

SHRI SUNIL SHASTRI: I will just take two minutes.

Sir, I would like to add here that the USA has already got the National Drought Council and the National Drought Commission. They have already come out with the National Drought Preparedness Act of 2002. A drought monitoring system has also been developed in the U.S.A. which gives the drought status and forecast, through a computerised network. मैं इस बात को यहां इसलिए रखना चाहता हूं ताकि इस तरह से अगर हम विचार करें तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को बड़ी उपलब्धि मिल सकेगी और हमारा भविष्य बेहतर होगा । मैं आंध्रप्रदेश के मुख्य मंत्री और वहां की सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने कुडप्पा में इस तरह की शुरूआत की है । उन्होंने एक बेस बनाया है जिस के माध्यम से वह किसानों की समस्याओं का निदान ढूंढ़ निकालते हैं । हमें भी इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि आंध्रप्रदेश की सरकार कुडप्पा में क्या कर रही है ? साथ-ही-साथ हम सभी को इस गंभीर समस्या के प्रति एकजुट होकर कार्य करना होगा क्योंकि हमारा यह मानना है कि good agriculture is good economics and good economics is good politics in the present times, and I would request the Government to appoint a study group immediately to develop a drought policy, followed by the setting up of National Drought Council, and, finally, enacting a national drought law.

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को कृषि मंत्री के संज्ञान में लाते हुए यह अनुरोध करुंगा कि आज हमारे समक्ष यह जो गंभीर समस्या है इस पर केन्द्र सरकार ध्यान देकर तुरन्त कार्यवाही करे और उन लाखों-करोड़ों लोगों को, जो आज भूख से मर रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास करे । बहुत बहुत धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Shri Satish Pradhan. You have four minutes.

SHRI SATISH PRADHAN (Maharashtra): I will try to finish within four minutes, Sir. There is drought situation in many parts of the country. But, unfortunately, we, the Members from small parties, have been facing the drought situation in the House continuously. This has been our grievance. Anyhow, let me come to the subject of today.

उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करुंगा, विनती करुंगा कि यह जो ड्राउट की परिस्थिति निर्माण हुई है, सूखे की परिस्थिति निर्माण हुई है, इसे सूखे की परिस्थिति मानकर ही इसका सामना करना चाहिए । इस विषय पर आप जरूर सोचें क्योंकि मेरा अनुभव रहा है कि जबसे कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में रही है, हम सूखे की परिस्थिति पर बात करते रहे हैं । यह एक नेचुरल कैलेमिटी अवश्य है, लेकिन सदियों से चली आ रही है । यह एक साइकल है, जिससे कुछ सालों में ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जाता है और जिसका सामना हमें करना पड़ता है । अब अगर सूखा हो जाए तो क्या क्या करना होगा, इस विषय में स्वतंत्रता के पूर्व कुछ नियम बनाकर रखे गए थे । इन नियमों का अमल करने से सरकार के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आती हैं, इसलिए इससे बचने के लिए सरकार ने एक दूसरा शब्द निकाल दिया कि यह ड्राउट नहीं बल्कि स्केयरसिटी है। स्केयरसिटी बोल दिया तो बहुत सारे मसलों से सरकार को छुटकारा मिल जाता है । मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके स्केयरसिटी जैसी परिस्थिति है ऐसा न कहें बल्कि ड्राउट कहकर ही परिस्थिति को फेस करें, जो ज्यादा अच्छा रहेगा । इससे हमारी जिम्मेदारी जरूर ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन हमें ऐसी परिस्थिति को फेस करना है । मैं समझता हूँ कि इस विषय पर गंभीरता पूर्वक सोचने की आवश्यकता है ।

महोदय, मैं जिस जिले से आता हूँ वह ठाणे जिला है। सुबह से मैं इस चर्चा को सुन रहा हूँ, मैंने सभी माननीय सदस्यों की बात सुनी । हर माननीय सदस्य एक ही बात कर रहा था कि वहां बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से वहां यह परिस्थिति निर्माण हुई । मैं बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में महाराष्ट्र में सभी जगह बारिश नहीं है, इसलिए वहां विकट परिस्थिति हो गई है, लेकिन इसके पहले गए महीने की 27 तारीख को ठाणे जिला में काफी बारिश हुई । वहां बारह घंटे में 24 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जिससे घर घर में आठ-आठ, दस-दस फीट पानी भर गया । वहां किसी के घर में न कपड़ा बचा, न मकान बचा, न खेती बची, न खेती का उत्पादन जो जमा करके घर में रखा था उसमें से कुछ बचा, पूरा का पूरा सब बह गया । बच्चों को स्कूल में जाने के लिए स्कूल अपनी जगह पर नहीं, घर से स्कूल जाने के लिए उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं । ऐसी परिस्थिति वहां निर्माण हुई । मैं माननीय उप-प्रधान मंत्री आडवाणी जी, जो गृह मंत्री भी हैं, उनका आभारी हूँ कि जब मैं और राम नाईक जी उनसे मिले तो उन्होंने

तुरन्त यहां सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक टीम भेज दी, लेकिन इससे आगे बढ़कर और कार्यवाही करने की, वहां मदद पहुंचाने की अत्यंत आवश्यकता है । इसके लिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि इस विषय पर आप तुरन्त ध्यान दें, वहां जो नुकसान हुआ है, जिसमें 61 लोग मर गए हैं, उनकी तरफ आप ध्यान दें और वहां मदद पहुंचवाएं ।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहूंगा, जैसा मैंने कहा कि बार बार हम इस परिस्थिति को फेस करते हैं, तो इसके लिए कोई एक एक्शन प्लान बनाया गया है? और, नहीं तो, इसको बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस विषय पर गंभीरता पूर्वक सोचने की बहुत आवश्यकता है । मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि बारिश नहीं हुई या थोड़ी सी हो गई और लोगों ने धान लगा दिया, लेकिन फिर बारिश नहीं हुई तो वह सब मेहनत खराब हो जाती है। बारिश नहीं आ रही तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए ? उस परिस्थिति में जब हमारे यहां का किसान एक प्रकार का कृषि उत्पादन नहीं कर सकता तो उसके बदले में वह दूसरा कौन सा उत्पादन कर सकता है, जिसकी वजह से वह अपने पांवों पर खड़ा हो सके, इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है और सिर्फ संशोधन ही नहीं, उस संशोधन के लिए उसे सब साधन उपलब्ध करके देने चाहिए और उसे किसानों तक पहुंचाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए । यदि यह हो जाए तो ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए भी हमारा किसान अपने पांवों पर खड़ा हो सकेगा ।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हम नाबार्ड के ज़रिए किसानों को कर्ज देते हैं । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि नाबार्ड की तरह से ही पानी इकट्ठा करने के कार्य के लिए यदि कोई किसान या ग्रुप्स आफ किसान कोई योजना बनाकर सामने आएं तो उनको लांग टर्म बेसिस पर साफ्ट लोन देने की कुछ व्यवस्था या इस तरह का कोई प्रावधान आप कर सकते हैं या नहीं, इस विषय पर सोचा जाना चाहिए । मैं महाराष्ट्र का एक अनुभव बताता हूं, जब वहां श्री वसंतराव नाइक जी मुख्य मंत्री थे, तो वहां हम दो तीन साल से लगातार सूखे को फेस कर रहे थे । उस समय वहां एक योजना बनाई गई - पानी आड़वा, पानी जिरुवा, पानी रोको और पानी जमीन में अंदर जाने दो। यह योजना बनाई गई, खेतों में जगह-जगह पर, जहां ओपन प्लेस हो वहां पर, स्कूल में जो प्ले ग्राउंड्स हैं उनमें भी तालाबों का निर्माण करो । उन तालाबों में बारिश का पानी रहेगा और वह बारिश का पानी जमीन के अंदर जाता था, इससे वहां का वाटर लैवल भी बढ़ गया था और इसका असर महाराष्ट्र में काफी अच्छा रहा । लेकिन साथ-साथ में मैं उपसभाध्यक्ष जी यह बताना चाहता हूं और नगर विकास मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि आप जो नगर का विकास करते हैं, सिटी का प्लान बनाते हैं या रूरल डेवलपमेंट एरिया वाले भी अपने-अपने गांवों का जब डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं तो ये सब डेवलपमेंट प्लान बनाते समय कुछ नहीं करते हैं । ये लोग सबसे पहले करते हैं कि वहां प्ले ग्राउंड की जरूरत है, वहां गार्डन बनाने की जरूरत है, वहां स्कूल बनाने की जरूरत है, वहां मार्किट बनाने की जरूरत है और इसके लिए जितने भी तालाब दिखते हैं, उन सब तालाबों को बंद कर देते हैं और उनके ऊपर यह सब कुछ बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में कहीं भी जहां तालाब है, जहां वाटर रिसोर्सिस है, वह किसी भी हालत में किसी को बंद करने की इजाज़त नहीं होगी । यदि आप यह नियम बनाएंगे तो वाटर लैवल आज जो गिर रहा है, हम उसे बचा सकेंगे और इसके कारण जो आज दुष्परिणाम हो रहे हैं, हम उनसे बच सकेंगे, हम उनसे निकल सकेंगे नहीं तो

फिर हमारी हालत बहुत बुरी होगी, हमारी आगे आने वाली सदी बहुत बुरी परिस्थिति में होगी । उपसभाध्यक्ष जी, मैं दो-तीन मिनट में कन्कलूड कर रहा हूं ।

उपसभाध्यक्ष जी, साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे महाराष्ट्र में हम छत्रपति शिवाजी की पूजा करते हैं, उनका आदर करते हैं और हर जगह बताते हैं कि राजा ऐसा होना चाहिए और उसे इस ढंग से काम करना चाहिए । शिवाजी महाराज ने उनके समय में एक कानून बनाया था कि हर घर के ऊपर से जो पानी नीचे टपकता है, उस पानी का वहीं कोई बंदोबस्त हो, वह पानी वहीं इकट्ठा किया जाए और वहां टैंक बनाकर उसमें पानी रखो, रिज़रवायर बनाकर रखो । यह इसलिए किया गया था ताकि कभी कोई आपत्तिजनक परिस्थिति का निर्माण होता है तो वह पानी आपके काम आएगा । कभी सूखे जैसी परिस्थिति आ जाए तो ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि पीने के लिए भी पानी नहीं है । आज महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना पर अमल करने का निर्णय किया है । मैं केन्द्रीय सरकार से यह कहूंगा कि मंत्री जी, आप इस पूरी योजना को समझकर यदि सभी राज्यों और प्रान्तों में इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो इसका बहुत असर होगा और इस सूखे से हम बच सकेंगे, मेरा यह मानना है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Mr. Pradhan, you have to conclude now.

SHRI SATISH PRADHAN: Sir, I am making some important suggestions which have not been made by other Members.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): You have already taken nine minutes. Please conclude now.

SHRI SATISH PRADHAN: I am concluding, Sir. मैं एक बात कहना चाहता हूं। सिर्फ महाराष्ट्र की बात बतलाता हूं कि वहां ऐसे दस हजार से ऊपर ऐसे तालाब हैं तो पूरे देश में कितने हैं? यह तालाब सदियों से वैसे के वैसे हैं। उसमें बहुत सारी बट्टी आकर इकट्ठी हुई है। यदि उस जगह पर ड्रेनिंग करने का कुछ बंदोबस्त करो तो रेलिंग करके वहां काफी जगह निर्माण होगी, वहां पानी बढ़ेगा और जिसका बहुत उपयोग होगा। मेरा आखिरी सजेशन है। वैसे बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय की पाबंदी भी रखना जरूरी है। उपसभाध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण बात कहना जरूरी है। हम पाईप के जरिए सब शहरों को देहातों से पानी लेकर आते हैं। इसकी वजह से देहातों में पानी कम होता है। इस तरीके से हम पानी दिल्ली में लेकर आते हैं, मुम्बई में लेकर आते हैं, चेन्नई में लेकर आते हैं, कोलकाता में लेकर आते हैं तथा और सब जगह लेकर आते हैं तथा वहां पर इस पानी का इस्तेमाल बहुत तादाद में होता है। इस पानी के इस्तेमाल को क्या हम कम कर सकते हैं? इसके लिए वाटर रिसाइक्लिंग की जरूरत है। एक आदमी के लिए हम जितना पानी इस्तेमाल करते हैं उसमें से सिर्फ 10 या 15 परसेंट पानी पीने के लिए या घर में खाना बनाने के लिए उसकी आवश्यकता रहती है। बाकी पानी की दूसरे कार्यों के लिए -नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, गार्डन इत्यादि के लिए जरूरत पड़ती है। क्या हम कोई व्यवस्था करके ऐसा प्लान नहीं बना सकते कि यह जो पीने का पानी है वह सिर्फ म्यूनिस्पल कारपोरेशन के एक वाटर टेप से आएगा जो किचिन में जाएगा और बाकी अन्य चीजों के लिए जो पानी की जरूरत है वह रिसाइक्लिंग किया हुआ हम इस्तेमाल करें। आज यह टेक्नोलॉजी हमारे देश में है। मुम्बई हाई में ओ0एन0जी0सी0 का जो

प्लेट फार्म है वहां समुद्र का पानी फिल्टर करके पीने के लिए यूज किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी हमारे यहां मुम्बई में है। हम सिर्फ शुरू में जो फाइव स्टार होटल हैं, फोर स्टार होटल हैं, थ्री स्टार होटल हैं या बड़े-बड़े रेस्टोरेंट हैं उसमें इसका इस्तेमाल करें। इण्डस्ट्रीज में तो इसको कम्पलसरी किया जाए। इसकी शुरूआत हमारी पार्लियामेंट से ही की जाए। तो इस तरह से हमें बाहर से पानी लाने में खर्चा कम होगा और वहां के लोगों को पीने का पानी मिलेगा। तो क्या हम इस विषय पर गंभीरतापूर्वक सोचेंगे। इसके लिए पैसा नहीं है ऐसा मत कहो, क्योंकि बाहर से पानी लाने का जो खर्चा है वह भी इससे ज्यादा है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे परमिशन दी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री ललितभाई मेहता (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय, देश में कई सालों से देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक विपदाएं आती रही हैं। कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार भूचाल आ जाता है, कई बार चक्रवात आ जाता है और आज हम सूखे की चपेट में आ पड़े हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो एक नक्शा है उसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल यह राज्य कभी सूखे की चपेट में नहीं आते थे और सबसे ज्यादा गुजरात और राजस्थान दो ही प्रदेश ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा ड्रोट एफेक्टेड रहते हैं। बाकी 5-6 राज्य ऐसे हैं जो ड्रोट एफेक्टेड रहते हैं। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति क्यों हुई ? परिस्थिति इस कारण हुई कि हमारे यहां जो पानी बारिश से आता है, हमारी जितनी भी आवश्यकता है, चाहे यह आवश्यकता हमारी निजी आवश्यकता हो, हमारी कृषि की आवश्यकता हो, हमारे उद्योग की आवश्यकता हो, हमारी बिजली के लिए आवश्यकता हो, जितनी भी आवश्यकता पानी की प्रति व्यक्ति है, उससे 80 गुना ज्यादा बारिश का पानी इस सृष्टि पर आता है । इस बरसात के पानी को संग्रह करने की व्यवस्था आजादी के 55 वर्षों में आज तक हमने नहीं की जिसके कारण इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है । महोदय, पहले समय में स्वयं व्यक्ति पानी के संग्रह की बात सोचता था, पानी के संग्रह की व्यवस्था करता था लेकिन आज हमारी मानसिकता यह बनी हुई है कि पानी की व्यवस्था जो करनी है, वह सरकार ही करे। सरकार द्वारा पानी की व्यवस्था करने के लिए और पानी के लिए हमारे देश में जो कानून बनते हैं, उन कानूनों के कारण भी हमारे सामने भारी दिक्कतें आती हैं, ऐसा मुझे लगता है। Antiquated Indian Easement Act, 1882, which still governs the water laws in the country. The Government has the sole prerogative to collection, retention and distribution of water in streams, lakes and in all other channels. उपसभाध्यक्ष महोदय, कल के अखबार में एक चित्र आया है । पटियाला के नजदीक जो सूखे का असर आया है, वहां पर साठ गांवों के किसानों ने मिलकर 24 घंटे में एक मिट्टी का डैम बना लिया है । वहां से एक नदी बह रही थी । अपनी फसल को बचाने के लिए उन्होंने उस पानी को रोक दिया । लेकिन हमारे जो पानी के कानून बने हैं, उनके तहत इस प्रकार का कार्य इल्लीगल है । सरकार इसको नहीं चलने देगी, यह समस्या है । इस प्रकार की स्थिति है। इस देश में पानी के जो कानून हैं, उसमें नागरिकों को, व्यक्तियों को या व्यक्तियों के समूह को यह स्वतंत्रता दी जाए कि पानी का संग्रह करने के लिए वे लोग जो भी कदम उठाते हैं, उनमें उनको सहूलियत दी जा सके । महोदय, देश में 66 हजार, 3 बिलियन क्यूबिक फीट पानी एक साल में बरसता है । उसमें से 42 हजार से ज्यादा मिलियन क्यूबिक फीट पानी समुद्र में बह करके चला जाता है । महोदय, देश में चार करोड़ हैक्टेयर जमीन खेती के लायक है । इस पानी का उपयोग खेती की जमीन के लिए अगर कर लिया जाए तो अनुमान यह लगाया गया है कि करीब

डेढ़ लाख करोड़ से साढ़े चार लाख करोड़ रुपये तक की खेत पैदाइश इस पानी से हम ले सकते हैं लेकिन पानी का व्यवस्थापन हमारे यहां नहीं है जिसके कारण इस देश में यह परिस्थिति निर्मित हुई है । महोदय, आज सभी प्रदेशों का उल्लेख किया गया । मैं गुजरात से हूं । यहां पर गुजरात का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया क्योंकि गुजरात में मानसून की जो पहली बरसात है, वह आ चुकी है, वह आ गयी है लेकिन गुजरात की परिस्थिति बिल्कुल विचित्र है । गुजरात के कई प्रदेश ऐसे हैं, सौराष्ट और कच्छ के प्रदेश, बनासकांठा जिला के प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जहां पर जमीन पत्थर की बनी हुई है । उसके कारण वहां पर पानी का संग्रह नहीं होता । गुजरात के बाकी जिले ऐसे हैं जिसमें 30 प्रतिशत जमीन ऐसी है जहां पर जमीन में पानी जाता है, बाकी पानी जमीन में भी नहीं जाता । उसके कारण गुजरात में बार-बार हमें अकाल का सामना करना पड़ता है, फैमीन का सामना करना पड़ता है । महोदय, गुजरात में 1997 में बाढ़ आयी थी और 650-700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था । 1998 में वहां पर चक्रवात आया और 1200 लोग मारे गये तथा 21 सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ । 2000-2001 में सूखा पड़ने के कारण दो सालों में सिर्फ कृषि पैदाइश का नुकसान 12000 करोड़ रुपये का गुजरात प्रदेश को भुगतना पड़ा, यह परिस्थिति गुजरात की है। आज गुजरात में भी मानसून की पहली बारिश आ गयी है । लेकिन मानसून की दूसरी स्पैल कब आएगी, यह नहीं कहा जा सकता । इसको ध्यान में रखते हुए गुजरात के बारे में भी भारत की सरकार को, केन्द्र सरकार को सोचना पड़ेगा । आज मैं एक और बात पर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा । गुजरात में 2,493.61 मिलियन क्यूबिक फीट पानी संग्रह करने की क्षमता बनी हुई है । लेकिन पिछले पचास सालों में तीन सालों को छोड़कर कई बार 400 मिलियन क्यूबिक फीट, कई बार 500 मिलियन क्यूबिक फीट और कई बार 100-150 मिलियन क्यूबिक फीट पानी का संग्रह होता रहा है और उसके कारण पीने के पानी की ज्वलंत समस्या पूरे गुजरात प्रदेश में है इसलिए इस समस्या को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और सुलझाना पड़ेगा ।

महोदय, गुजरात राज्य 1960 में बना और 2002 में 42 सालों में वहां कई अकाल और सूखे आए हैं और गुजरात की इस समय जो विशेष परिस्थिति है, उसको भी सरकार को ध्यान में रखना होगा । हमारे पास जो पानी आता है, उस पानी का हम किस तरह से उपयोग करें कि जिसके कारण देश में कहीं अकाल भी न हो, कहीं बाढ़ की परिस्थिति भी न आए । पानी का व्यवस्थापन, वाटर मैनेजमेंट, यह सबसे ज्यादा ध्यानाकर्षण करने वाला प्रश्न रहना चाहिए और अगर हम यह करने में सफल रहते हैं तो मुझे लगता है कि इस परिस्थिति का हल हम ढूंढ पाएंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री डी0पी0 यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । यह विषय अति महत्वपूर्ण है और गंभीर भी है । सवाल यह नहीं है कि महज़ सूखा शुरू है और किसान परेशान है । जितनी गंभीरता को हम लोगों की आंखें देख रही हैं, यह विषय उससे भी ज्यादा गंभीर है । मसलन मौसम ने धोखा दिया, बारिश हुई नहीं और किसान की खेती सूखने लग गई । दूसरी तरफ जो ज़मीन का पानी था, उसका लेवल नीचे चला गया । मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि जितना मुझे अनुभव अभी उत्तर भारत के कई प्रदेशों में जाकर देखने को मिला कि पीने के पानी की विकट समस्या लोगों के सामने आने को तैयार खड़ी है । नदियां सूखने लगी हैं, किसान की स्थिति तो यह है कि जिन किसानों ने इस गलतफहमी में अपने खेतों में फसल की बुवाई शुरू कर दी थी कि आगे आने वाले मौसम में बारिश से फसल ठीक हो जाएगी, उन किसानों को आज

यह डर सताने लगा है कि जो बीज उन्होंने मोल लेकर खेत में डाला था, वह पैसा भी उनको वापस बीज के रूप में फसल के रूप में मिल सकेगा या नहीं । सवाल यहीं खत्म नहीं होता मान्यवर । चारे की विकट समस्या गांवों में पैदा हो गई है । पानी न होने की वजह से, बारिश न होने की वजह से, वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से जो किसान के पशु हैं, उनके खाने के लिए हरा चारा पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं है और किसान बेचारे की ज़िंदगी तो उसके पशुधन पर आधारित होती है । अगर मौसम भी धोखा दे जाए तो पशु का दूध बेचने के बल पर किसान यह सोचता है कि उसके परिवार की जीविका चल जाएगी लेकिन यहां वह स्थिति भी इसलिए उलट होने लग गई है कि किसान के खेत में अगर चारा ही पैदा नहीं होगा तो वह अपने पशु को क्या खिलाएगा और किस तरह से अपने परिवार का भरण-पोषण करेगा ? मैं समझता हूं कि यह विषय और भी ज्यादा गंभीर इसलिए हो जाता है कि जो बड़े-बड़े महानगरों में गांवों से और किसानों के घरों से दूध की पूर्ति होती है, अगर यह चारे की समस्या इसी तरह बनी रही और बरसात न होने की वजह से किसान की खेती इसी तरह चौपट हो गई तो कई समस्याएं आकर खड़ी हो जाएंगी जिनको आज हम गंभीरता के साथ नहीं देख रहे हैं, वे कल को बहुत गंभीर होकर खड़ी हो जाएंगी । वैसे तो जहां तक मेरी जानकारी है और मेरी सोच है, आज़ादी मिलने के 54 वर्ष तक बाकी किसी भी क्षेत्र में काम हुआ हो, मैं इस विषय पर जाना नहीं चाहता लेकिन किसान, किसान के खेत और किसानों की समस्या और परेशानी और दैवी आपदाओं के लिए जो काम होना चाहिए था, इस मुल्क की सरकारों ने वह काम नहीं किया है । आज भी किसानों की स्थिति यह है कि उसका बच्चा जो स्कूल जाता है, वह पहले खेत में काम करके, चारा काटकर अपने पशुओं को खिलाकर तब स्कूल जाता है ।

दूसरी तरफ गांव की किसान के घर की गर्भवती महिलाएं आज भी देखने को मिलती हैं कि प्रसव होने के एक-एक महीना पहले तक अपने सिर पर बोझा ढोती रहती हैं। इसका मतलब साफ है कि आजादी मिलने के 54 वर्ष बाद भी किसान के साथ न्याय नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जो इस वक्त सूखा पड़ने से पैदा हो गई है, उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य, अभी हमारे एक साथी खान साहब, सांसद बोल रहे थे। मैं तो अभी पिछले दिनों अलवर गया था। राजस्थान का पहला जिला है जो दिल्ली से लगा हुआ है। खेतों के बीच से गुजरते हुए देखा कि किसान ने खेतों में जो बाजरा और मक्का की फसल की बुवाई की हुई है, इस आसरे पर कि बारिश हो जाएगी और फसल ठीक हो जाएगी, इसकी जो कोपल हैं और जो ग्रोथ है, पेड़ को आगे बढ़ाती है, यह ऐंठने लगी है और उसकी जड़ सूखने लगी है। यह स्थिति महज राजस्थान में ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में यहां तक स्थिति पैदा हो गई है कि गन्ने की फसल को किसान की पक्की फसल के रूप में देखा जाता है बल्कि मैं कह सकता हूं कि कैश क्रॉप के नाम से गन्ने की फसल को जाना जाता है। विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के पास अगर पचास बीघा जमीन है तो चालीस बीघा जमीन में गन्ना लगा होता है। यही स्थिति पंजाब की है, यही स्थिति आन्ध्रा की है और यही स्थिति गन्ना पैदा करने वाले दूसरे प्रदेशों की है। गन्ना जो कि पक्की फसल किसान की समझी जाती है, वहां भी पानी की परेशानी पैदा हो चुकी है। जब किसान का मन फर्टीलाइजर लगाने का होता है कि फसल में फर्टीलाइजर लगाकर पानी लगा दिया जाए, वह किसान आज अपना मन मसोसकर चुप बैठा है क्योंकि फर्टीलाइजर लगाने के बाद एकदम पानी की जरूरत होती है। पानी है नहीं, वाटर लेवल नीचे जा चुका है, नदियों में पानी आ नहीं रहा है। दिल्ली से जाते हुए आप और हम लोग भी देखते हैं कि यमुना नदी सूखने के कगार पर खड़ी है। ऐसी स्थिति में सरकार कोई ऐसा

5.00 p.m.

कदम किसानों के प्रति या उन तमाम लोगों के प्रति नहीं उठाएगी तो मैं समझा हूं कि एक गंभीर समस्या पूरे देश के सामने पैदा हो जाएगी। सवाल यह उठता है कि वह किसान जिसका आधार ही खेती है और महज किसान नहीं, किसान का आधार खेती है, खेती से उसका परिवार चलता है। लेकिन महोदय, महज यह किसान की ही पेरशानी नहीं है, यह परेशानी पूरे मुल्क के लोगों की है। अगर अनाज की आपूर्ति नहीं होगी, चारे की आपूर्ति नहीं होगी तो स्थिति सबके सामने एक ऐसी समस्या बनकर खड़ी हो जाएगी जिसकी जरूरत आज यह है कि माननीय कृषि मंत्री जी यहां मौजूद हैं। अभी हमारे साथी सांसद कह रहे थे कि चौधरी अजित सिंह ने खेती न की हो, शायद मैं समझता हूं कि किसान के घर में भी अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो विरासत में उसको इतनी जानकारी मिल जाती है। हमने ग्रन्थों में पढ़ा है और सुना है कि वीर अभिमन्यु ने गर्भावस्था में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। किसान के घर में अगर कोई बच्चा भी पैदा हुआ है तो विरासत में उसको खेती से ताल्लुक रखने वाली किसान की परेशानियों और समस्याओं के बारे में इतनी जानकारी हो जाती है कि उसे और जानकारी की जरूरत नहीं रहती है। मैं समझता हूं कि चौधरी अजित सिंह जी खुद इस देश के महान स्वर्गीय चौधरी चरणसिंह जी के बेटे हैं, किसान के रूप में और किसान परिवार के रूप में जाने जाते हैं। मेरी यह सोच है कि इस सूखे की स्थिति को देखते हुए कम-से-कम जो किसान खेती करता है या खेती से ताल्लुक रखने वाला जो भी परिवार है, उसके बच्चे को मुफ्त शिक्षा देने का काम सरकार करे। खेती को, फसल को दी जाने वाली दवाइयां हैं, बीमारी में काम आने वाली दवाइयों की मुफ्त वितरण की व्यवस्था हो। जो किसान के ऊपर कर्जा है, जब उसके यहां फसल नहीं हो रही है तो कर्जा चुकाने की स्थिति में किसान नहीं आ पाएगा। किसान के ऊपर जो कर्जा है वह ब्याज मुक्त तो होना ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उसकी अदायगी और भुगतान में भी कोई ऐसा नियम जरूर लागू होना चाहिए, ताकि किसान को राहत की सांस आए। मैं कहना चाहता हूं कि उत्पादन के लिहाज से मेरी जानकारी में वर्ष 2000-2001 में आटा और मैदा का उत्पादन 2443 हजार टन हुआ था।

परंतु वह उत्पादन 2002 में 2.32 प्रतिशत घटकर 2,386 हजार टन पर आ गया । अगर यही स्थिति रहती है तो खाद्यान्नों में कई विकट समस्याएं पैदा हो जाएंगी । दूध सही रूप में शहर वाले लोगों को भी नहीं मिल पाएगा । छोटा बच्चा, जो दूध पीकर बड़ा होता है, जिसके लिए दूध एक खुराक के रूप में जरूरी है, अगर गांव से आने वाला दूध नकली और दोषपूर्ण होगा तो निश्चित रूप से इस मुल्क के सभी लोगों पर इसका असर होगा ।

[उपसभापति पीठासीन हुईं]

उपसभापति महोदया, मैं यही कहूंगा कि आज की सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार को कोई उपयोगी कार्य योजना लागू करनी चाहिए । किसान के हित में, किसान के परिवार के हित में, खेती से ताल्लुक रखने वाले, खेती पर आधारित तमाम लोगों के हित में कोई ऐसी योजना और नियम जरूर लागू करने चाहिए जिससे सूखे की स्थिति से निपटने में सरकार का सहयोग और सहायता मिले और किसान की निराशा भरी आंखें जिस परेशानी में हैं उसके लिए कोई हल निकल सके । धन्यवाद ।

SHRI DINESH TRIVEDI (West Bengal) : Madam, let us congratulate, through you, our new President, Dr. Abdul Kalam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have already done that. You are late.

SHRI DINESH TRIVEDI: Madam, I, on my behalf and on behalf of my party, Trinamul Congress, would like to extend our heartiest congratulations to our new President, Dr. Abdul Kalam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Actually, what happens is, some Members just walk in and out of this House as per their convenience. They do not know the record. It was already announced.

SHRI DINESH TRIVEDI: Madam, but I was not there. On behalf of my party...

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not a question of Party, it is the House, and you are a part of this House.

SHRI DINESH TRIVEDI: Madam, I had checked up, but I was misinformed by the Table Office.

THE DEPUTY CHAIRMAN: But I had asked each and every Party Member to put his or her congratulations on the Board. It was done collectively. Anyway, we accept it. Now, there are three more names. I am not going to entertain any new names because, yesterday, very strictly, I announced that the Members who want to speak should give their names at the proper time. Sometimes, you suddenly decide to speak on some issue and send the slip. Because of that, all our calculations go wrong. Now, there are three names with me. Shri N.K. Premachandran. Mr. Premachandran, please don't think that you can speak for 52 minutes.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): Madam, I will take five minutes only.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two other Members also. But you can speak for five minutes.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, the point is, we come under 'others' category. Though we belong to a political party, 'others' are classified as a separate group. And we are called after the Members of all the political parties have finished. So, my humble submission is, during the rotation, some preference should be given to 'others'.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will see to it that you all don't come at the tail-end. We will think of it. But please take five minutes. Fifty-two minutes are for all the 'other' Members.

SHRI H.K. JAVARE GOWDA: Madam, they have given him a chance to speak on behalf of them.

THE DEPUTY CHAIRMAN: But I have not received any such information. चलिए, अभी समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, आप ही देर से जाएंगे ।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, many a time, this matter has been discussed elaborately in this august House. I also express my grave concern as far as the latest drought situation is concerned. Madam, we are well aware that during last year, in the month of July and August, in the same session, *i.e.*, in the Monsoon Session, this House had elaborately discussed the flood situation. But all the predictions have proved wrong, and a severe drought has affected all parts of the country now, especially, the northern parts of our country. As has been very clearly mentioned, the delay in the arrival of the monsoon, in Rajasthan, Madhya Pradesh, Orissa, Andhra Pradesh, and even in Delhi, is creating a great deal of apprehension in the minds of the people as a whole. Last year, we had a discussion on another monsoon-related problem, floods, and this year also, we are talking about the delayed monsoon. In this connection, I would like to say that though the State of Kerala, which I represent, is not so seriously affected by the problem of delayed rainfall, there is a severe decline in the rainfall, especially, the South-West Monsoon has not been so good this year. Normally, the South-West Monsoon starts in early June, but so far, the rainfall has not been effective or intensive in the state of Kerala also. That shows the gravity of the whole situation which is prevailing in this country. The delayed monsoon or inadequate rains are affecting the livelihood of not only the agriculturists, but the livelihood of all the people of this county. Madam, in my State, the people are mainly dependent on hydro-electric power. But the water level of various dams has considerably gone down. The statistical data shows that if it continuously goes down for a period of one month, there would a total power cut in the State of Kerala, because the State is totally dependent on hydro-electric power. If this is the situation in a State like Kerala, which normally has a rich rainfall, we can just imagine what could be consequences of inadequate rainfall in the States like Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan and other such States.

Madam, now, I would like to point out one thing regarding the Indian Meteorological Department. Even in the last week of May, the Indian Meteorological Department had predicted that heavy rain, continuous rain, intensive rain, would come, and they had even warned the fishermen and the agriculturists in this regard. They told them "we are giving you a

warning that heavy, intensive, rain, continuous rain, is going to fall in the last week of May or in the beginning of July." But nothing has happened. All the predictions of the Indian Meteorological Department have been proved wrong. I am not finding any fault with our scientists or with our Indian Meteorological Department, but the thing is, that something has gone wrong. That has to be admitted. Even now, an intensive rainfall has not taken place; the South West Monsoon has not come.

Madam, about the scarcity of water and the water management system, I would like to say one or two things. Now-a-days, Madam, we are having the advantage of the developments in science and technology, especially, in space technology, ocean development, etc. We have advanced a lot in all those fields. But even after all these advancements, even after having made tremendous progress in these fields, we are not able to change the traditional water management policy in our country. We are still pursuing the same water policy which is in existence for the last so many decades. Even after so many new things have come into existence in the field of science and technology, space technology, ocean development, we are not able to meet the challenge. We are not able to predict in advance about these natural calamities and take precautionary measures at the appropriate time so as to meet the challenge. That is the position even after so much of progress in science and technology. We know that so many dams have been constructed. I am not going into the details of all these, due to paucity of time. A large number of down-trodden people, Adivasi people, people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, have been evacuated from their places, and huge dams were constructed. Now, what is the result of all this? Madam, when something like drought or floods take place, mainly, the down-trodden people are affected. Here also, due to drought, the sufferers are the agricultural labourers, because of poverty and joblessness. They have no job because the agricultural fields have nothing to offer them. So, the people all over the country are being greatly affected by this delayed monsoon, and, this would affect the whole country in the near future.

Madam, I would also like to say one thing about the alternative planning of river management. We are having plenty of water. So many water disputes are already going on in this country. I am not going into all those disputes. There is the Cauvery water dispute, there is the Mullaperiyar dispute, and so on. But I am not going into all those things because it is under the consideration of the Government, the Cauvery Water

Authority, and even court proceedings are going on. So, the river management policy has also to be re-vamped so as to exploit and make the maximum use of it. That is my another suggestion. Now, I come to the other point. In the last Session, we had discussed the issue of scarcity of water, and many distinguished Members of this House had made valuable suggestions. One of the suggestions was that we should have a specific policy on rain water harvesting. We should evolve an effective plan to have rain water harvesting. I would like to know from the Government what steps they have taken to implement the policy relating to rain water harvesting. We know that we are not able to use the rain water.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Is it not a State subject? The water management is a State subject, and the State should formulate a policy to do the rain water harvesting. You should tell your State as to how to harvest the rain water.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: But, the programmes have been of the Centre. The water management programme is being managed by the Centre, and even the funds are being allocated by the Centre. Many of these programmes have been funded by the Centre. So, the Centre should formulate some policy so that this could be developed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: In Delhi, some NGOs are doing water harvesting in homes. If everybody does the same thing, there will be no wastage of water, and in that event, you do not need any assistance from anybody. *(Interruptions)* In Delhi itself, they are doing it, and the water table has gone up.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: In Tamil Nadu, the NGOs are doing the rain water harvesting. My suggestion is that the Government of India has to take an initiative to formulate some programme so that this awareness could be created in the minds of the people. It does not matter whether the rain water harvesting comes under the jurisdiction of the Centre or the State.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Secretary-General told me that rain water harvesting is being done even in the Rashtrapati Bhavan.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: An indepth study has to be made regarding the problem of inadequate rainfall in this year. Shri Sunil Shastri has already drawn the attention of this House to this problem. As far as the problem of weather change is concerned, this is not a phenomenon which

is confined to India. This phenomenon of weather change is there throughout the world. That unexpected change of the climatic condition is all over the world. It is a world wide phenomenon. So, an indepth study has to be made. According to my experience, it is prevalent due to deforestation. Disputes are going on against those people who are encroaching the forest land, destroying the forests, creating an ecological imbalance and who are a threat to environment. So, more stringent provisions have to be made to protect the forests and environment and to maintain an ecological balance. These are the points which I wanted to make. I would also like to make a reference to the relief measures. Effective relief measures have to be made. In the last two years, the norms for getting the relief under the National Calamity Relief fund have been changed. This situation has to be reviewed. That is my suggestion. Most of the States, especially, the southern States, may not be getting proper relief because of the change in the relief norms. With these words, I conclude. Thank you.

SHRI H.K. JAVARE GOWDA (Karnataka): Madam, a severe drought situation is hovering over the entire country except two or three States. The State of Karnataka is the most severely hit State this time. The situation is that during the pre-monsoon period, Karnataka used to have a little rainfall. But, this time, the monsoon has not been in full swing in Kerala yet. This has caused a drought-like situation in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka. The late monsoon has not at all started in the northern parts of the country. We are all facing the severe effect of the failure of Monsoon and we are hearing the problems of the people as such. In Karnataka, there is a drinking water problem because of the depletion of the water table. In north Karnataka, there is a district called Gadag. It is a district headquarters. The people in that area were not getting water from the municipality, for 45 days. Now, they are getting water once in ten days.

Another important factor is that the greenery has dried. There is no fodder for the cattle. Another problem is, there were two pre-monsoon showers. The farmers sowed the seeds and put the manure. But the entire thing has withered now. The farmers who sowed the seeds and put the manure lost that much money also. All the tanks and river-beds in the entire Karnataka have gone dry. There is no water at all. We are facing this kind of a grave situation. It is for the first time, in the past 15 years, that Karnataka is facing such a severe drought situation. Therefore, Karnataka has to be declared a drought-hit State immediately. The South-

West Monsoon is the main source of rains in the country, particularly, Karnataka. But it has not yet come. We have to wait for the South-East Monsoon, which comes after two months. Now, there is absolutely no chance of any rains at all. Under these circumstances, without the help of the Central Government, it is very difficult for the Karnataka Government to protect the livestock and help the farmers.

There is another disturbing factor, which has been reported by almost all the newspapers in Karnataka. It is that, the villagers are migrating to the cities in search of employment. But there are no employment opportunities. There is absolutely no work in the cities. Under these circumstances, the Central Government has to come forward to help the States.

Though we are boasting that we are very much advanced scientifically, our meteorological department is not able to predict the Monsoon correctly. Had they made correct predictions about the Monsoon, the farmers could have saved their seeds and the money invested on manure. He could have waited for another 15 or 20 days, and this sort of waste would have been avoided.

Last year, the farmers in the country had a good crop. But they suffered because there was a fall in the prices of agricultural products. Therefore, many farmers committed suicide. This year, the farmers have sown the seeds and put the manure, but there is no rain. So, they continue to suffer.

As far as the broader aspect of the matter is concerned, it is a fact that every State Government in the country is almost bankrupt. They are not in a position to pay even the salaries. All the cheques have bounced. This is the financial position of the States. Every farmer in the country, particularly, in view of the drought, looks towards the sky. He believes only in nature, that is, God, hoping that the rains would come. He has lost faith in all the machinery, including the Executive and the people's representatives. With the little resources that we are having, we are trying to help the farmers. In spite of this pitiable situation, this Government is not coming forward to help the farmers. Last year, this Government had not come forward to rescue the farmers. It did not take any steps to prevent the farmers from committing suicide. There was no rain for two months. But there was no help from the Central Government. The Central Government has not made any plan to tackle the problems. There is an

1713 GIPMR/03—19

urgent need to chalk out some plans to tackle the problems. I urge upon the Central Government to declare Karnataka a drought-hit State and release, at least, an amount of Rs.300 crores for relief works. Thank you.

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY (West Bengal): Madam, today we are debating the drought situation. Last year we were debating the flood situation. This cycle will continue. I do not think it is within our hands to control it. The reasons for this change of drought-flood cycle which is out of our hands are global warming, climate change, population explosion, environment and deforestation. A word of warning: Afghanistan is having a three-year drought period. Pakistan is having a two-year drought period. Drought has advanced to Rajasthan and Gujarat and I do feel that drought is creeping up on us from the North West. We should take heed on this. The remedies are two-fold, short-term and long-term. So far as short-term remedies are concerned, which is with the Agriculture Ministry, they are usually in the form of providing resources to the States to meet various immediate requirements of the drought situation like loss of crops, etc. which the other Members have elaborated upon. The problem is, there is a perpetual confrontation between the Centre and the States. I do not think this can go on for a long time because in all such cases the State usually mentions a certain figure. The Centre makes its own assessment and then this debate goes on, usually, with a lot of ill-feeling on both sides. I think the Centre should be careful because it has been our experience -- it may be a coincidence or may be unintended -- that the States whose Governments are not part of the National Democratic Alliance, tend to get lesser drought relief than those States which seem to be more favoured. I am specifically talking of my own State, West Bengal. It may well be a coincidence, it may well be unintended, but unfortunately, that is the situation which has been created. The only solution for this problem is a National Water Grid. There is no other answer for this drought problem. Now the National Water Grid also will not take place because -- forget about the Indus Water Treaty with Pakistan; forget about the Ganges Water Treaty with Bangladesh -- we have within our own country the Cauvery dispute, the Narmada dispute, the Sutlej-Yaumna Link dispute. Before, we make a National Water Grid, we should first try and set down amicably and sort out our own internal disputes. Unless we have a system like the Ganges-Cauvery link, like the Himalayan Canal, this cycle of drought-flood will continue to plague us for years and years to come. I do appreciate that this is perhaps outside the scope of the activities of the Agriculture Ministry. But, unless, this is done, we will never find a solution to this problem. As a

matter of fact, I would go a step further. This point came up this morning during the Question Hour when the Indo-Nepal Treaty was being discussed. The key to the drought situation and flood situation in the Ganges Valley is Nepal. Unless India and Nepal sit down and work out a joint water management treaty or a joint water management system, India will continue to be plagued by this cycle of drought and flood. So the Government has to pay serious attention to it. So far as other remedies are concerned, we do not have to go very far outside the country to study it. It is obviously to bring up the level of ground water. Rain water harvesting, as you said just now, is a State's responsibility. We do not have to go abroad. We merely have to go to Ahmednagar district in Maharashtra in our country and see the place called Ralegaonsidhi under Shri Anna Hazare. It is a miracle of really not modern but traditional water management. And, if this is put into effect in most of the drought-prone States of our country, I think, the severity of drought conditions will not be felt as widely as it is being faced today. The problem is again an attitudinal problem. We consider these measures during times of emergency only. When the emergency period passes, these measures are allowed to slip. I do think that the Governments, both at the Centre and in the States, must really devote their complete and united attention to this major problem. Otherwise, we will be repeating these debates at the appropriate seasons for many years to come. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, all the Members have spoken. The Minister to reply now...*(Interruptions)*... No; I will not allow anybody now. I cannot make any favours or disfavours. Only those names, which came in the morning, would be entertained. I said it yesterday and I don't want to go back on my own words and my own ruling. It is already 5.30 p.m. and we have to finish this now. Yes, Mr. Minister.

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : माननीय उपसभापति महोदया, हम लोग 12:30 बजे से देश के विभिन्न भागों में जो सूखे की स्थिति पैदा हुई है, उसके बारे में बहस कर रहे हैं । यह चिंता का विषय है । माननीय सदस्यों की जो चिंता है, वह स्वाभाविक है क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 65 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या कृषि पर आधारित हैं और हालांकि हमारी जी0डी0पी0 का केवल 24 प्रतिशत तकनीकी आधार पर कृषि का हिस्सा है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों पर या किसानों पर कोई विपदा आती है तो उसका असर हमारे देश पर व्यापक होता है । यह चिंता स्वाभाविक है और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार भी इस चिंता से ग्रसित है और हम इसके लिए अलर्ट भी हैं और जो भी तैयारी हम कर सकते हैं, वह कर रहे हैं । साथ ही यह भी तय है कि मानसून आने में देरी हुई है, लेकिन अभी हम इसको ड्राउट डिक्लेअर कर दें, यह सही नहीं है क्योंकि पहले तो यह केन्द्रीय सरकार का

अधिकार नहीं है । श्री शंकर राय चौधरी जी ने अभी कहा कि केन्द्रीय सरकार इसको ड्राउट डिक्लेअर करे, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वह किसी क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर सके । लेकिन हमारी चिंता है और उसके लिए हमें जो तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए हम अलर्ट हैं । सब सदस्यों को पता है कि सूखे की क्या स्थिति है, फिर भी मैं बताना चाहता हूं, जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं - आंध्र प्रदेश के मैम्बरों ने कहा कि हम सिर्फ नार्थ इंडिया या मिडिल इंडिया की बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है IMD उसके अनुसार जो स्टेट अफेक्टिड हैं, उनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश हैं । इन सबके बारे में हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि यहां सूखे की स्थिति है ।

प्रो0 रामदेव भंडारी : बिहार में दोनों हैं, एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ सुखाड़ है।

श्री अजित सिंह : बिहार में और भी बहुत सी चीजें हैं, जिनसे बिहार ग्रसित है, वह सवाल यहां नहीं है, लेकिन जहां सूखे की स्थिति गंभीर है, वे ये राज्य हैं लेकिन अगर बिहार में ऐसी स्थिति है तो वहां की सरकार के टच में हम हैं, वे हमको बता सकते हैं और उनके बारे में भी वही व्यवहार होगा जो और राज्यों से होगा, कोई अलग व्यवहार बिहार के साथ होने वाला नहीं है । यह भी सच है कि इस साल मानसून लेट है और जो हमारे 70 प्रमुख रिज़रवायर हैं, उनमें भाखड़ा को छोड़कर सबमें पानी इस बार कम भरा हुआ है । बल्कि जो हमारा दस साल का ऐवरेज है, यदि उसको लें तो इस साल करीब 66 प्रतिशत पानी ही इन रिज़रवायर्स में है । स्थिति चिंताजनक है, लेकिन इसको अभी से ड्राउट डिक्लेअर कर दें, यह सही नहीं है क्योंकि पहले तो यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है और दूसरा हम नहीं मानते कि अभी ऐसी परिस्थिति हुई है कि अभी से हम इन सारे क्षेत्रों को ड्राउट ग्रसित डिक्लेअर कर सकें । अभी मेरे पास 2:00 बजे की रिपोर्ट है, बहुत लोगों ने कहा कि हमारा मैट्रोलाजिकल डिपार्टमेंट ठीक रिपोर्ट्स नहीं देता और उसकी जो भविष्यवाणी है, वह ठीक नहीं है और उनको और पैसे देने की जरूरत है । कुछ लोगों ने, हमारे कलराज मिश्र जी ने कविता में बताया भी कि और बहुत से तरीके हैं ड्राउट के बारे में मालूम करने के, यह सही बात है कि और बहुत से तरीके हैं लेकिन ड्राउट या किसी नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में ऐकुरेट फोरकास्ट की जहां तक बात है, वह हमारे देश की ही मैट्रोलाजिकल डिपार्टमेंट की बात नहीं है, अमरीका, जहां पैसे की कमी नहीं है या और भी कोई, चाहे इंग्लैंड को देख लीजिए, वहां भी फोरकास्ट बहुत बार गलत हो जाती है । मैट्रोलाजिकल डिपार्टमेंट आपको पोसिब्लिटीज़ बता सकते हैं, ऐग्ज़ेक्टली इस दिन बारिश होगी या दो दिन में हो जाएगी, वे इस बारे में पोसिब्लिटीज़ या प्रोबेब्लिटीज़ बता सकते हैं ।क्योंकि इतने ज्यादा वेरिएबिल फैक्टर्स हैं। कहीं आपके देश से 10 हजार किलोमीटर दूर एक क्या परिस्थिति हवा में बन जाती है उसका असर यहां की बरसात में भी हो सकता है। इसलिए जो भी फोरकॉस्ट होती है उसे मैं फिर कहना चाहूंगा कि कोई डेफनिट गारंटी उसमें नहीं है, एक प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी की बात उसमें होती है। आज जो दो बजे की रिपोर्ट मेरे पास है उसके हिसाब से आज उड़ीसा में कई जगह बारिश हुई है, आन्ध्रा में इंटीरियर एरियाज को इंक्लूड करते हुए काफी बारिश हुई है, छत्तीसगढ़ में बारिश कल भी हुई थी आज भी हुई है। ईस्ट यू0पी0 में कई जगह बारिश शुरू हो गई है, साउथ राजस्थान में बारिश हुई है। कोटा में, पिलानी में कल भी बारिश हई थी और आज कंटीन्यू कर रही साउथ राजस्थान में। गुजरात में और महाराष्ट्र में आज बारिश हुई है।

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : राजस्थान में मामूली बौछार पड़ी है, कोई बरसात नहीं हुई है।

श्री अजित सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि मौसम विभाग का यह आकलन है अगले 3-4 दिनों में बरसात आ सकती है और इस तरफ बादल आ रहे हैं, यह सम्भावना है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो सूखे की स्थिति आज के दिन बन रही है उसमें क्या परिस्थिति है। उसमें सरकार को क्या करना चाहिए वह कर रही है। लेकिन जो रिपोर्ट शायद थोड़ी सी आशा की किरण हम लोगों के दिल में जागे तो वह मैं आपको बतला रहा हूं इसमें कोई खराब बात नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी बारिश हुई है। यह सही है जैसा मैंने कहा कि सूखे की परिस्थिति है, मानसून लेट है, दो हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं। यह चिंता स्वाभाविक है। जहां पर फसलों पर असर पड़ने की बात है, सबसे ज्यादा असर तो जो कोर्स ग्रेंस हैं और जो ऑयल सीड्स हैं उन पर आलरेडि असर पड़ गया है। कुछ irretrievable हैं, कुछ जगह और फसल पैदा की जा सकती है। लेकिन मेरे पास जो 15 तारीख के आंकड़े हैं उसके अनुसार बाजरा में 93 लाख हेक्टेयर में हर साल बुआई होती है। लेकिन 15 तारीख तक 56 लाख हेक्टेयर में होती है उसमें 31 लाख हेक्टेयर में ही अभी बुआई हुई है। इसी तरह ज्वार वगैरह में सब में यही हाल है। सोयाबीन, ग्राउंड नट और पल्सेज में भी पिछले साल के मुकाबले में इस 15 तारीख तक जितनी बुआई होनी थी उतनी नहीं हुई है। जहां तक चावल का सवाल है, चावल के बारे में हर साल 406 लाख हेक्टेयर में बुआई होती है। लेकिन 15 तारीख तक सिर्फ 72 लाख हेक्टेयर में ही होती है और इस साल 15 तारीख तक 71 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। हमारे यहां 80 प्रतिशत से ज्यादा चावल ट्रांसप्लांटेड होता है। इसमें अभी समय है। विशेषज्ञों ने भी कहा है तथा जो किसान मेरे पास आते हैं उनसे भी बातचीत हुई है कि उसमें अभी समय है और जो बासमति वगैरह है उसमें तो आप 15 अगस्त तक बुआई कर सकते हैं। यह जरूर है कि यदि यही मोएस्चर की कमी रही तो उस ट्रांसप्लांटेड राइस में प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। छत्तीसगढ़ और झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में कुछ ऐसा इलाका है जहां डायरेक्टली राइस बोया जाता है, वहां पर इस फसल के ऊपर काफी नुकसान हुआ है। जहां तक सोयाबीन की बात है उसमें सबसे ज्यादा असर हुआ है। सोयाबीन बड़ी सेंसेटिव क्रोप्स है। जनरली इसको 15 जुलाई तक बो दिया जाता है। अगर एक-दो दिनों में बारिश हुई तो उसको बचाया जा सकता है वरना सोयाबीन की बुआई नहीं हो सकती है। मूंगफली अभी तक इस बार कम बोई गई है। अगर 31 जुलाई तक बारिश हो गई तो उसमें कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। माननीय जनेश्वर मिश्र जी ने जो कहा है, जो तैयारी हमने की है उसमे आल्टरनेटिव क्रोप्स के बारे में भी हमने प्रदेश सरकारों से कहा है कि वह तैयार रहें, सीड्स की अवेलेबिलिटी के बारे में मालूम करें। माननीय जनेश्वर मिश्र जी ने कहा कि सरकार आल्टरनेटिव क्रोप्स को कैसे करा पाएगी इनकी किसानों की कोई जानकारी नहीं है। मिश्र जी, यह सही बात है कि हमारे यहां खेती का जो उत्पादन बढ़ा है तथा जो आज हम सरप्लस स्टेज में हैं उसकी सरकार की उसमें हिस्सेदारी कम है और किसान की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। किसान यह भी जानता है कि आल्टरनेटिव क्रॉप कब और कहां पैदा करनी होती है । सरकार के बताने का वह इंतजार नहीं करता है । आप अपने किसान का इतना कम आकलन मत करिए कि जब सरकार बताएगी कि कौन सी आल्टरनेटिव क्राप हो तभी वह उसको बोने का काम करेगा । ड्राउट बहुत बार किसानों ने फेस किया है, फ्लड बहुत बार फेस किया है । वह जानते हैं कि अगर सोयाबीन नहीं होना है या बाजरा नहीं होना है तो कौन सी दूसरी क्राप यहां पर पैदा की जा सकती है ।

समस्या आलरेडी है, जैसा मैंने कहा । बहुत से सदस्यों ने कहा कि केन्द्रीय सरकार, कृषि मंत्री सिर्फ यही कह देंगे कि यह तो प्रदेश सरकारों का सब्जैक्ट है। आपने ठीक कहा । मैं यही कहने वाला हूं । यह प्रदेश सरकारों का सबजैक्ट है लेकिन केन्द्रीय सरकार ने, हमारे ऐग्रीकल्चर सैक्रेटरी ने, सब स्टेट्स के ऐग्रीकल्चर सैक्रेट्रीज़ से मीटिंग की है । हमने एक ज्वाइंट सैक्रेटरी को हरेक स्टेट के लिए नोडल ऑफिसर बनाया है । हम प्रदेश सरकारों को बता रहे हैं कि क्या हमारी राय में उन्हें करना चाहिए और हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं । क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अभी ड्राउट डिक्लेयर करने की स्थिति चाहे न हो, लेकिन उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए । एक हफ्ते बाद या दस दिन बाद जब भी कोई स्टेट ड्राउट डिक्लेयर करेगी तो हमारा ऐक्शन प्लान रेडी होना चाहिए और उसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह से जागरूक है । अब प्रश्न है कि सरकार क्या कर सकती है ? केन्द्रीय सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या जब ड्राउट की आएगी तो वह पीने के पानी की आएगी । उसके बारे में रेलवे की भी जरूरत है, वाटर रिसोर्सिज़ मिनिस्टरी की भी जरूरत है । प्रदेश सरकारों को भी हमने कहा है कि आप लोकेट कीजिए कि कहां से पानी का स्रोत है जो उनको पहुंचाया जा सकता है । हमने प्रदेश सरकार को यह भी कहा है - जैसा उत्तर प्रदेश से हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में भी सरकारी ट्यूबवैल बहुत अच्छी हालत में नहीं हैं - उनको फौरन रिपेयर कराया जाए । ग्रामीण प्रदेशों में ज्यादा बिजली देने का इंतजाम किया जाए और जैसा मैंने कहा है कि सीड्स किस तरह के हो सकते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में वह हमें सारी जानकारी दें । अगर वहां कमी है तो हम केन्द्रीय स्तर पर उसमें कुछ मदद कर सकते हैं । फूड फॉर वर्क एक प्रोग्राम है । जो भुखमरी की बात लोगों ने कही । एक दम अगर सूखा पड़ जाएगा तो सही बात है कि गरीब लोगों के सामने भुखमरी की समस्या आ सकती है । इसके लिए हमने अभी से कहा है कि आप ऐसे एरियाज़ आइडेंटीफाई कीजिए जहां पर फूड फॉर वर्क से सुविधा मिल सकती है और हम भी एफ.सी.आई. से और फूड मिनिस्टरी से टच में है कि जो ड्राउट प्रोन एरियाज हैं, जो ड्राउट अफैक्टिड डिक्लेयर हो सकते हैं, वहां जल्दी से जल्दी कैसे फूड ग्रेन पहुंचाया जा सकता है । उसकी तैयारी हम कर रहे हैं । समस्या जैसा मैंने कहा कि सिर्फ 24 प्रतिशत जी.डी.पी. की नहीं है, समस्या और व्यापक हो सकती है । अगर किसानों के सामने समस्या आएगी तो उसके लिए हम पूरी तरह से एलर्ट हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज ही 15 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है । वहां पर प्रदेश सरकार किसी भी रैवेन्यू का रियलाइजेशन बंद कर देती है । आप सबको मालूम है कि प्रदेश सरकार इसमें क्या-क्या कर सकती है । वह इस संबंध में कदम उठाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं । जैसा मैंने कहा कि हम भी उनके टच में हैं कि हम क्या कर सकते हैं । अभी आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों ने कहा कि एक रिलीफ फंड होना चाहिए । 11th फाइनेंस कमीशन में डिज़ास्टर्स के लिए एक रिलीफ फंड हर स्टेट को देते हैं । जो राजस्थान में 225 करोड़, आंध्र प्रदेश में 218 करोड़, महाराष्ट्र में 173 करोड़, गुजरात में 177 करोड़, और उड़ीसा में 120 करोड़ है । यह पैसा इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए 11th फाइनेंस कमीशन के द्वारा हरेक सरकार को दिया जाता है और उसके बाद भी अगर और जरूरत पड़ी तो केन्द्रीय सरकार के पास एक कंटिनजेंसी फंड है । वैस्ट बंगाल के माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूंगा कि इसमें कोई कनफ्लिक्ट नहीं है कि केन्द्रीय सरकार और प्रदेश सरकार में कोई कनफ्लिक्ट हो । प्रदेश सरकार अगर हमसे कहेगी कि ड्राउट अफैक्टिड एरियाज़ हैं, हमारा फंड खत्म हो गया है तो हम एक टीम भेजेंगे और वह टीम हरेक जगह जाकर खुद चैक नहीं करने वाली है । जो प्रदेश सरकार के अफसर

कहेंगे, उसी बात को वह मानती है । हम अफसर इसलिए नहीं भेजते हैं कि वह जाकर चैक करें कि प्रदेश सरकार सच्ची खबर दे रही है या नहीं दे रही है । वह सिर्फ इसलिए जाते हैं कि कंटिनजेंसी फंड में कुछ काम डिज़ास्टर्स के लिए अलाउड हैं और कुछ काम अलाउड नहीं हैं । अगर आप कोई पक्की सड़क बनाना चाहें जहां disaster हो गया है, उसमें कंटिंजेंसी फंड का इस्तेमाल नहीं हो सकता है । इस तरह के कुछ मापदंड बने हुए हैं, तो केन्द्रीय टीम उनसे जाकर यही बात करती है कि उन मापदंडों के अंदर कितना पैसा आपने खर्च किया है और कितना हम उसमें मदद कर सकते हैं ?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu) : What is the amount for Tamil Nadu?

SHRI AJIT SINGH: This is on yearly basis. The money is Rs.113 crores. You have taken the first instalment. The second instalment is Rs.42 crores. As far as the Central Government's contribution is concerned, it is 75% and that of the State's is 25%. The total of Tamil Nadu's share is Rs.113 crores. Out of that, around Rs.85 crores is the Central Government's contribution and Rs.28 crores is the State's contribution. It is given in two instalments. The first instalment has already been taken by your Government and the second instalment is still due.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: What about Orissa?

SHRI AJIT SINGH: Those things you can have at any time--how much is available and how much is not available. *(Interruptions)* We can't go and spend it for the State Government.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: You said that some amount is given by the State Government and some by the Central Government.

SHRI AJIT SINGH: 25% by the State and 75% by the Central Government.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: In the case of Orissa Government, it is not ready to spare Rs.30 crores. I would like to know whether the Orissa State Government can get Rs.90 crores or not.

SHRI AJIT SINGH: These are the rules laid down by the Eleventh Finance Commission. But, still, let me remind the hon. Member that in the case of Orissa, our Prime Minister has gone over there and made special announcements, whenever there has been a disaster over there. The Centre has tried to help even those States which can't use the money, that comes to them normally. The hon. Member from West Bengal can be sure that there is no question of any step-motherly treatment for any State.

(Interruption) West Bengal has not asked us for any help, at least, for the last two years that I know of, under this scheme. So, please don't say that. We wish you don't need this money, you don't ask for it. But, if you ever need it, we will be there to help you like any other State.

The Crop Insurance Scheme is another scheme. ...*(Interruptions)*...

श्री सुरेश पचौरी : ज़रा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी कृपापूर्वक ध्यान दीजिए ।

श्री अजीत सिंह : आप बैठे हुए हैं और मध्य प्रदेश पर हम ध्यान न दें, ऐसा कैसे हो सकता है ? मध्य प्रदेश पर तो ध्यान ही ध्यान है । आप जानना चाहते हैं कि कितना पैसा दिया है? करीब 70 करोड़ दिया है ।

श्री सुरेश पचौरी : ठीक है । 64.23 करोड़ का इन्होंने जो प्रपोज़ल भेजा है नगरीय पेयजल की व्यवस्था के लिए और एक मेमोरेंडम भी दिया है आपकी सरकार को, उसको भी स्वीकार कर लें ।

श्री अजीत सिंह : आप जो मेमोरेंडम भेजेंगे, जो आप यहां सदन में कहेंगे, जो वहां के मंत्री कहेंगे, उस पर हम सदैव विचार करते हैं, करेंगे । यह समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है, किसी एक प्रदेश की सरकार की नहीं है । जैसा मैंने कहा कि यह किसानों पर जो आपदा आई है, इसका बड़ा व्यापक असर पड़ेगा । अगर उनकी परचेसिंग पावर खत्म हो जाती है तो यह नहीं है कि कृषि का 24 परसेंट हिस्सा कम होकर 20 परसेंट हो गया या 18 परसेंट हो गया, क्योंकि 65 परसेंट से ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ेगा अगर कोई फसल नष्ट होती है । तो इसके बारे में हम जागरूक हैं और जो मदद हम कर सकते हैं, वह करने के लिए हम तैयार हैं ।

क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में उड़ीसा के कुछ माननीय सदस्यों ने सवाल उठाए थे । यह दुख की बात है कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को इन तीन-चार राज्यों ने जहां इस बार सूखे का ज्यादा असर पड़ा है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को अभी तक अपने प्रदेश में लागू नहीं किया है । उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और करीब 18-19 राज्यों ने इसको अपने प्रदेश में लागू किया हुआ था । क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में अभी बहुत कमियां हैं, मैं मानता हूं क्योंकि उसमें जो टेस्ट होता है, जैसा आपने कहा कि 50 प्रतिशत से कम या ज्यादा, यह इंश्योरेंस प्रत्येक किसान की फसल नष्ट हुई या नहीं हुई, इस पर आधारित नहीं है । एक एरिया में कितनी फसल कम हुई या ज्यादा हुई, यह उस पर आधारित है । हम उस एरिया को छोटे से छोटा करने के लिए प्रयत्नशील हैं । हम चाहते हैं कि प्रत्येक किसान की कितनी उपज हुई, उसको अगर हम देख सकें और स्पेस टैक्नोलोजी के द्वारा आजकल हम यह देख सकते हैं। लेकिन इसको हम छोटा करने के प्रयत्न में हैं। हम चाहते हैं हरेक किसान इसका फायदा उठा सके। लेकिन आपने एक सवाल यह भी उठाया था कि जो किसान लोन लेते हैं, सिर्फ उनको ही यह सुविधा प्राप्त है, यह नहीं है। यह है कि कोई भी किसान स्वेच्छा से इसका फायदा उठा सकता है, जो लोन लेते हैं, उनके लिए जरूरी है। जो लोन नहीं ले रहे हैं, वे भी इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो लोन ले रहे हैं, उनको इसमें इन्श्योरेंस कराना जरूरी है। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक बहुत अच्छी स्कीम है। उड़ीसा, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश जहां पिछले पांच-दस सालों में बहुत व्यापक डिजास्टर हए हैं, कभी फलड, कभी साइक्लोन, कभी सूखा, इन प्रदेशों ने

इसका अच्छा फायदा उठाया है। जहां इस प्रकार के डिजास्टर नहीं होते हैं, वहां शायद अभी लोगों की समझ में नहीं आया है कि इससे कितना फायदा हो सकता है। हम चाहते हैं कि वे प्रदेश भी आगे आएं। जो दो हैक्टेयर के सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनके प्रीमियम का पचास प्रतिशत हिस्सा उसमें सरकार देती है। किसान को पूरा प्रीमियम उसमें नहीं देना पड़ता। उसमें सरकार की भागीदारी है। छोटे किसान के लिए पचास प्रतिशत हिस्सा सरकार उसमें देती है। जैसा मैंने कहा कि यह प्रदेश सरकार का अधिकार है। उत्तर प्रदेश में अब तक 15 जिलों को डिक्लेयर सूखाग्रस्त किया है। जैसे ही कोई सरकार यह महसूस करती है, और उनके अलग-अलग मापदंड हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, उत्तर प्रदेश सरकार में अगर किसी जिले में पचास प्रतिशत फसल नष्ट हुई तो वे उसको सूखाग्रस्त घोषित कर देते हैं। फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि हम इसके प्रति जागरूक हैं। जो भी हम कर सकते हैं और हम इस समय यहां से एक तैयारी कर सकते हैं। जब सरकार उसको ड्राउट प्रोन एरिया डिक्लेयर कर देगी, तो वे जो एक्शन ले सकते हैं, ले लेंगे। जो उनको रिलीफ फंड से पैसा मिला है, जब वह खर्च हो जाएगा या इससे पहले भी वे हमसे कहेंगे कि आप आकर देखिए क्या स्थिति है, हम एक टीम फौरन जरूर भेज देते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा कि वह टीम उनपर चैक करने लिए नहीं है, वह टीम जानकारी लेकर यह देखती है कि कौन सा पैसा हम दे सकते हैं, किस क्षेत्र में नहीं दे सकते हैं,सिर्फ इसलिए वह टीम जाती है। इसलिए यह जो सूखे की परिस्थिति है, हम इस टाइम यही कर सकते हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं। स्टेट गवर्नमेंट को आगाह करें, हमारे जितने यहां पर अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं उनसे को-आर्डिनेट करें, एक कंटिनजेंसी प्लान बनाएं और साथ ही यह आशा करें, हालांकि मैटरोलोजी डिपार्टमेंट की शायद अभी तक फोरकास्ट ठीक न रही हो। लेकिन हम आशा करेंगे कि अब उनकी फोरकास्ट ठीक रहेगी। इन शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभापति : श्रीमती बिम्बा रायकर आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हैं।

SHRIMATI BIMBA RAIKAR (Karnataka): Madam, I would like to seek, through you, a clarification from the hon. Minister. Once Karnataka was known for its greenery and today it is suffering from drought. Last year, our demand was Rs. 900 crores. We went in a delegation, not once or twice, but three times. But we did not get anything from him. The second point is, there was a hailstorm. For this hailstorm, we had asked for Rs. 200 crores. Lastly, we agreed to Rs. 100 crores. Even this we did not get; not even a single pie. The hon. Minister was very sympathetic to us. He spoke very nicely with us; in words, but not in kind. And, today, Karnataka is suffering like anything. We have got 177 talukas and 28 districts. Out of these 28 districts -- I would like to inform the hon. Minister -- more than 20 districts are suffering from drought. A Committee was sent and the Committee gave a very good report. The Committee said, 'Karnataka is suffering like anything and money should be given to it.' But nothing has been given.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are you seeking a clarification or making

a speech? Otherwise, I will have to ask everybody. You just put specific questions.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Madam, I would like to know from the hon. Minister what help he is going to give us. Is he going to give us any help or he wants to send another team? If he wants to send another team, it is welcome. But he should send the team immediately, take the Report from that team, and see that Karnataka gets some help.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, I have one suggestion. This discussion was on drought. You can very well deal with drought because it is a matter of crop. But certain Members raised questions about water management. It would have been nicer if the Minister for Water Resources Development was here to answer those questions. There were so many Members who asked about water harvesting, National River Grid Schemes, dams, etc.

SHRI AJIT SINGH: Madam, agriculture includes everything. If there is shortage of fertilizer, worst affected is agriculture; if there is shortage of diesel, worst affected is agriculture. So, Petroleum Ministry gets involved. The Rural Ministry can get involved because all the work is done in rural areas. So, Agriculture Minister may not be all pervasive, but Agriculture Ministry is all pervasive. *(Interruptions)* In every debate on agriculture -- prices, drought, flood, power or anything -- I am used. They also know it. They are highlighting the problem of the farmers, not just one particular crop or issue. We try to answer as many as we can. Their suggestions may not be directly relating to the Agriculture Ministry, but we note them down. We try to pass them on to our colleagues because we understand that agriculture is affected by everything.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Agreed. But you see when the question of National River Grid Scheme...*(Interruptions)*...

SHRI AJIT SINGH: It is for you to decide which questions I should answer. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: That's what I thought. It would be nicer...*(Interruptions)*...

SHRI AJIT SINGH: But we are the nodal Ministry for drought relief. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: If these questions are going to go on...*(Interruptions)*...

SHRI AJIT SINGH: Let me answer because that will affect others. ...*(Interruptions)*...*Andhra* Pradesh asked for Rs. 1000 crores. Last year also they asked for Rs. 1000 crores. Karnataka has asked for Rs. 900 crores; Maharashtra has asked for Rs. 700 crores. No State has asked for less than Rs. 500 crores. The problem is Eleventh Finance Commission laid down certain parameters as to what kind of work is allowed under this contingency funds. And it was done in consultation with the Chief Ministers. States agreed that these are the parameters under which the money would be given from the Contingency Fund. In drought conditions, the items include cost of supplying drinking water through tankers, etc.; agricultural input subsidy to small and marginal farmers for crop damage exceeding 50 per cent; provision of fodder and cattle camps; emergency supply of medicines; and gratuitous relief to the destitute. In extreme cases, cost of employment generation and material cost of relief work can also be met from this fund. One question I had not answered earlier. The Hon. Member from Orissa had mentioned the Drought-prone Area Programme. In last eight years, more than Rs. 1000 crores have been allocated through the Ministry of Rural Development under this scheme. Let me again repeat that all States have a Drought Contingency Plan. It is up to the State Governments, how updated they keep, how alert they are on that. We, on our part, are asking them to give us information, and we are giving them whatever help we can.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is your problem? You have already made your speech. ...*(Interruptions)*...

SHRI AIMADUDDIN AHMED KHAN (DURRU): Madam, he has talked about the Centre-State relationship. You are aware, for the last so many months Indian troops are there in the border areas of Rajasthan. They are consuming a lot of water. The underground water reservoirs are going down. Crops have been destroyed by the troop movements. They are still there. They are neither moving forward nor backward. Could he use his good offices either to compensate farmers or ensure that there is some alternative supply of water to these people who have been deprived?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Does it come under his Ministry?

SHRI AIMADUDDIN AHMED KHAN (DURRU): Yes, Madam, it is the nodal agency.

SHRI AJIT SINGH : Madam, the Defence Ministry has already given compensation to the farmers, because their crops have been destroyed and their farmlands have been used.

SHRI AIMADUDDIN AHMED KHAN (DURRU): No, Sir, the demand that was sent by the State Government has not been met by the Ministry.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is the Defence Ministry.

SHRI AIMADUDDIN AHMED KHAN (DURRU): The compensation paid was only one-third of what was asked for. In regard to the underground water reserves...(Interruptions)...

उपसभापति : आपकी क्या समस्या है? ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : मैडम, माननीय मंत्री जी ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : ऐसे तो सारा हाउस ही चलता रहेगा, I have to adjourn the House now फाइव मिनट में you say whatever you want to say.

श्री के. रहमान खान : कर्नाटक का जवाब ही नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा ...**(व्यवधान)**...

SHRI AJIT SINGH: Madam, we can have a discussion on it again, after two weeks.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, we cannot have another discussion on this. ...*(Interruptions)*...

श्री सुरेश पचौरी : मैडम, मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ में बारिश हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 262 मिलीमीटर बारिश होनी थी जो केवल 159 मिलीमीटर हुई है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ की भी स्थिति यह है कि 64.5 प्रतिशत बारिश वहां होनी की संभावना है आपके मौसम विभाग के अनुसार। अभी तक छत्तीसगढ में सेंट्रल टीम नहीं गयी है। मध्य प्रदेश को पैसा नहीं मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जो खास बात है वह मैं यह कहना चाहूंगा कि चौधरी चरण सिंह के पूत से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे ब्यूरोक्रेसी द्वारा दिए गए आंकड़ों के जाल में फंस जाऐंगे और किसानों का जो असली दर्द है उसको वे बंटा नहीं पाऐंगे। उन्होंने यह बिल्कुल नहीं कहा कि सूखा जो कई प्रदेशों के लिए हर वर्ष की समस्या बन गया है उसके लिए कोई दीर्घकालिक समेकित योजना बनायी गयी है वाटर ग्रिड मिशन की मरूस्थल सुधार की ...**(व्यवधान)**... उसके लिए कोई जवाब नहीं है ...**(समय की घंटी)**...

उपसभापति : अब आपने सवाल पूछ लिया है ...**(व्यवधान)**...

श्री अजित सिंह : मैडम, उसके बारे में बहुत स्कीम्स हैं, वाटर कंजरवेशन स्कीम है ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : अभी आपको इमोशनली ब्लैक मेल कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री अजित सिंह : बहुत सी स्कीम्स हैं ...**(व्यवधान)**...ये पूछते जाएंगे और आप एलाउ करती जाएंगी तो मैं बोलता जांउगा...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : अजित सिंह जी की जब भी बात होती है ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : चौधरी साहब का नाम लेते हैं ...**(व्यवधान)**...अब खतम ...**(व्यवधान)**...Now, no more questions. सबका जवाब दे दिया है...**(व्यवधान)**...कह दिया है..I have heard about Bihar. *(Interruptions)* What is it? What is it? *(Interruptions)* Maharashtra has got the money. *(Interruptions)*

श्री सतीश प्रधान : महाराष्ट्र को कब पैसा मिला ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी: सूखे के कारण वहां चारा नहीं पहुंच पा रहा है ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश प्रधान: सुरेश भाई, अब आपका हो गया है ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, you are from which State? *(Interruptions)* I have allowed two - three Members from Karnataka; so, please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI N.R. DASARI (Andhra Pradesh) : Madam, I have been in this House for the last four years. I would like to bring this to your notice and to the notice of the hon. Minister of Agriculture; never before in this country the floods and drought have been so widespread as we are witnessing today. This is what has emerged from this discussion. So, I would like to request you, without any offence to the Government -- of course, the Government is quite busy with...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am going to adjourn the House within two minutes.

SHRI N.R. DASARI: I want the Minister to come before this House with a contingency plan within a week or ten days.

श्री सतीश प्रधान : मैडम, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं केवल कि सरकार का नियम यह है कि सब बैंकों का जो रिजर्व है उसमें से 18 परसेंट पैसा किसानों के लिए या फसल के लिए खर्च करना है। हमारा कोई भी बैंक इसका पूरा इस्तेमाल नहीं करता है। तो क्या माननीय कृषि मंत्री जी यह विषय दोबारा फाइनंस मिनिस्टर से लेकर इस विषय पर कोई निणर्य लेने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि किसानों को जो लोन दिया जाता है उसको जो बारिश है उसके साथ कुछ जोड़ने की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे।

उपसभापति : आप एक या आधे मिनट में जवाब दे दीजिए।

श्री अजित सिंह : मैं सिर्फ छोटा सा जवाब दूंगा वरना जो ऋण की बात है वह तो बहुत लम्बी है। ये कह रहे हैं कि 18 परसेंट जो बैंक्स को खर्च करना पड़ता है वे नहीं करते हैं। यह सही बात है। सरकार ने एक कानून बनाया है और यह व्यवस्था बनायी है, कानून नहीं है कि जो 18 परसेंट में शार्ट फाल है उसको आरआईडीएफ, रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में बैंक्स दे देते हैं ...। और उसको इस्तेमाल हम गांवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए करते हैं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The discussion is over now. The House is adjourned till 11 o'clock tomorrow.

The House then adjourned at six of the clock,
till eleven of the clock on Friday, the 19th July, 2002.

MGIPRRND—1713 GIPMR/03—375 Copies.